

जनता द्वारा जमा वाहनों, लर्निंग लाइसेंस और लाइसेंस नवीकरण के कितने आनलाइन आवेदन दिल्ली परिवहन विभाग में लंबित

टोलवा ट्रस्ट और रक्षा द सेवियर फाउंडेशन के सांझा वस्त्र वितरण समारोह के लिए मंजू अरोड़ा ने दिए वस्त्र



अभिषेक राजपूत

नई दिल्ली। सामाजिक कल्याण के कार्यों में निस्वार्थ भाव से सहयोग देने वाले लोग सदैव प्रेरणास्रोत होते हैं। हाल ही में श्रीमती मंजू अरोड़ा ने अपने उदार भाव और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ज़रूरतमंदों के लिए वस्त्र दान करें। यह योगदान न केवल वस्त्र प्रदान करने तक सीमित है, बल्कि समाज में सेवा और सहानुभूति की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। टोलवा ट्रस्ट और रक्षा द सेवियर फाउंडेशन इस मानवीय पहल पर हृदय से मंजू अरोड़ा का आभार व्यक्त करते हैं। मंजू अरोड़ा का यह सहयोग उन असहाय और वंचित परिवारों के लिए वरदान सिद्ध होगा जिन्हें छोटे-छोटे संसाधनों की भी कमी रहती है। वस्त्र का यह दान केवल तन ढकने का



साधन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीने की आशा भी प्रदान करता है। हम सबके लिए यह कार्य प्रेरणास्पद है, क्योंकि समाज को बेहतर बनाने में हर दान और हर सहयोग की अपनी अहम भूमिका होती है। सामाजिक परिवर्तन तभी संभव है जब दया, करुणा और सहयोग की भावना हर व्यक्ति के मन में जागे। टोलवा ट्रस्ट और रक्षा द सेवियर फाउंडेशन एक बार पुनः श्रीमती मंजू अरोड़ा को उनके इस उदार योगदान और सेवा भाव के लिए धन्यवाद करते हैं। उनके इस सहयोग से हम सभी को यह विश्वास मिला है कि संवेदनशील हृदयों के जुड़ने से समाज में सकारात्मक बदलाव अवश्य संभव है।

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग भारत देश का पहला परिवहन विभाग जहां सबसे पहले

1. आनलाइन आवेदन फेस फ्री सेवा शुरू हुई
2. ड्राइविंग लाइसेंस टैस्ट एटीएस द्वारा शुरू किए गए
3. वाहनों की जांच (फिटनेस) एटीएस द्वारा शुरू की गई
4. लर्निंग लाइसेंस या शिक्षार्थी लाइसेंस एक अस्थायी कानूनी अनुमति आनलाइन टेस्ट प्रक्रिया द्वारा शुरू की गई

इन सभी सेवाओं को शुरू करने के पीछे एक ही कारण जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया की “जनता को कोई परेशान नहीं करें” और जनता को क्षेत्रिय कार्यालयों में धक्के नहीं खाने पड़े/ चक्कर नालगाने पड़े। दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग दिल्ली द्वारा दिखाया गया खाबब बहुत खूबसूरत था और उसमें सभी खो गए और उसका फायदा उठा कर दिल्ली परिवहन विभाग ने दिल्ली में चल रहे (14) चौदह क्षेत्रिय कार्यालयों को बिना किंसा पूर्व सूचना / बिना अनिवार्य राजपत्रित सूचना जारी किए समेट कर (4) चार में कर दिया और विभाग का बड़ा खर्चा बचा लिया और जनता का छोड़ दिया धक्के खाते रहने के लिए।

यह हम प्राप्त विश्वस्तु सुओं के अनुसार बता रहे हैं, “दिल्ली की आम जनता को तो छोड़ दो एक राजपत्रित अधिकारी भी स्वयं आनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में



सक्षम नहीं” अर्थात् जनता को आनलाइन आवेदन करने और फीस कटवाने के लिए साइबर कैफे की मदद अनिवार्य हो गई जो पहले वह क्षेत्रिय कार्यालय में जाकर मुफ्त में कटवा लेते थे यही नहीं परिवहन विभाग ने कोई अधिकृत साइबर कैफे और कार्य की फीस भी लागू नहीं की जिससे जो चाहें जनता से कितने ही फीस सर्विस के नाम पर बढ़ोता रहे, आनलाइन आवेदन प्रक्रिया जनता की दृष्टि में एक है पर एक आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत कम से कम तीन अलग अलग विभाग कार्यरत है

1. एनआईसी
2. आधार कार्ड विभाग
3. बैंक

और किसी की भी सर्विस काम नहीं करे तो आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी और आपकी जानकारी में होगा हम अपने समाचार पत्र में कई बार सबूतों के साथ यह बताते रहे हैं की जनता इन तीन विभाग के चक्कर में फीस कटवा ही नहीं पा रही और साइबर कैफे के चक्कर पर चक्कर लगाने को मजबूर है।

किसी तरह आनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई तो वह आवेदन विभाग में ठंडे बस्ते में ही बंद पड़ा रहता है, कार्यालय के चक्कर ज्यादा लगा लो तो कोई भी कारण लगा कर उसे पेंडिंग में डाल देते हैं चाहे वह उस एप्लिकेशन के संबंधित आबेकान हो या नहीं हो, जनता के लिए शुरू हो जाता है फिर से

साइबर कैफे का चक्कर और तय्युचत विभाग के चक्कर, आखिर कितना सुखद है ना दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग द्वारा शुरू किया गया आनलाइन फेस फ्री आवेदन प्रक्रिया, जो काम पहले कार्यालय में हाथों हाथ होने की संभावना रहती थी अब तो वह भी सिर्फ और सिर्फ होते हैं मध्यस्ता के माध्यम से, दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग के आला अधिकारी से निवेदन स्वयं एक टीम बनाकर आनलाइन फेस फ्री आवेदन पर हो रही इस धांधली की निष्पक्ष जांच कर और स्वार्थी कर्मचारियों पर लगाम लगा कर जनता को दिखाए गए सुखद खाबब को सुखद बनवाए।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत पिकी कुंडू महासचिव टोलवा ट्रस्ट



सभी जनमानस को सूचित किया जाता है की 21 सितंबर दिन रविवार को दोपहर 1 बजे डाबडी मोड पर ट्रस्ट द्वारा दाल चावल के लंगर का आयोजन किया जा रहा है, इसी दिन ट्रस्ट से जुड़े नए सदस्यों को जिन्हें अभी तक उनके पहचान पत्र (आई कार्ड) प्राप्त नहीं हुए है प्रदान लिए जाना निश्चित किया गया है। भंडारे में उपस्थित होकर भंडारा ग्रहण करें और ट्रस्ट से जुड़े नए सदस्य साथ ही अपने पहचान पत्र प्राप्त करें।

प्राचीन भारतीय साहित्य और धर्मग्रंथ हमें प्रेरणा देते हैं “पितृ वचन पालन”, “भ्रातृ प्रेम”, “पत्नी की मर्यादा” और “त्याग” की



अभिषेक राजपूत
प्राचीन भारतीय साहित्य और धर्मग्रंथों के आलोक में, संयुक्त परिवार और नैतिक मूल्यों की परंपरा न केवल सामाजिक ढांचे का, बल्कि आत्मिक-सांस्कृतिक समृद्धि का भी आधार रही है। आज के संक्रमणकालीन दौर में ये मूल्य, आधुनिक बदलावों के बीच, पुनः संतुलन की मांग करते हैं। प्राचीन भारतीय सोच और धर्मग्रंथों में संयुक्त परिवार रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य परिवार, प्रेम, कर्तव्य और नैतिकता के सबसे बड़े शिक्षक हैं। रामायण में प्रभु राम के जीवन से “पितृ वचन पालन”, “भ्रातृ प्रेम”, “पत्नी की मर्यादा” और “त्याग” के उदाहरण मिलते हैं। राम का वनवास स्वयं के लिए नहीं, परिवार और समाज के लिए था—समर्पण, त्याग तथा कर्तव्यनिष्ठा का आदर्श। महाभारत में पाण्डवों और कौरवों के रिश्तों की पेचीदगियाँ परिवार के मध्य नैतिक द्वंद, उत्तरदायित्व और सत्य-न्याय को दर्शाती हैं। विदुर नैतिक, भीष्म धर्म का

त्याग, युधिष्ठिर का धर्मपालन—ये सब परिवार और समाज में नैतिकता के प्रतीक हैं। वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र और स्मृति-ग्रंथों में परिवार की व्यवस्था—“संयुक्त परिवार” को समाज और धर्म के पालन का श्रेष्ठ स्थल बताया गया है। परिवार के मुखिया को “कर्माधिकारी” और सभी को उत्तरदायी एवं सम्मिलित दायित्व निभाने वाला माना गया। नैतिक मूल्य व संयुक्त परिवार की भूमिका संयुक्त परिवार केवल आर्थिक इकाई नहीं था—यह “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना का जीता-जागता उदाहरण था। “आचार्य देवो भव”, “पितृ देवो भव”, “मातृ देवो भव” जैसे श्लोक सम्मान और सेवा का मार्ग दिखाते हैं। भरण-पोषण, शिक्षा, सुरक्षा, भावनात्मक सहयोग—सबका दायित्व समवेत रूप में निभाया जाता था। मनीषियों ने ‘सुसंस्कार’ परिवार को संस्कारों का पाठशाला बताया; “सा प्रथमा संस्कारशाला परिवारः”। अर्थात् परिवार ही सबसे पहली शिक्षा देने वाला स्थान है।

संक्रमण काल: बदलते मूल्य और चुनौतियाँ
1. आधुनिक भारत में शहरीकरण, प्रवासन, शिक्षा और रोजगार ने परिवार को छोटे-छोटे इकाइयों में बदल दिया है।
2. निजता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत संपत्ति की चाह के कारण भावनात्मक निकटता और जिम्मेदारी कुछ हद तक कम हुई है।
बुजुर्ग कभी-कभी उपेक्षित रहते हैं; संयुक्त परिवार की सामाजिक सुरक्षा की दीवार कमजोर हुई है फिर भी, “त्याग, सहयोग, संवाद, प्रेम”—ये मूल्य आज भी बचते हैं; अक्सर आते ही रिश्तों का महत्व उजागर होता है।
स्वस्थ संबंधों के लिए साहित्यिक एवं दार्शनिक संदेश भारतीय साहित्य में परिवार के संबंध और संस्कारों को सर्वोच्च बताया गया—“मनुष्य का पहला धर्म परिवार की रक्षा करना है”।
रामायण की ‘जनक-सीता-संवाद’, महाभारत का युधिष्ठिर-भीम-संवाद, संत कवि तुलसीदास की चौपाइयाँ—इनमें परिवार, प्रेम और उत्तरदायित्व की विमर्श बार-बार मिलता है।

कबीरदास कहते हैं, “घर तू खोज, घर में मिले, घर की बात अनोखी”—अर्थात्, जीवन की सच्ची शांति और प्रेम घर-परिवार के अंदर ही मिलती है।
निष्कर्ष: परिवारिक संबंधों की मधुरता के लिए आज जरूरत है -
1. संतुलन लाने की;
2. पुराने मूल्यों का सम्मान और आधुनिकता की सकारात्मकता को अपनाने की।
3. संवाद, सहयोग, विश्वास, त्याग और बड़ों के प्रति सम्मान—ये प्रेमपूर्ण परिवार की नींव हैं।
4. परिवार भले आज छोटा हो, पर संस्कार, प्रेम और ज़िम्मेदारी की डोर कभी छोटी नहीं होनी चाहिए।
5. त्योहार, परंपराएँ, और परिवारिक आयोजन रिश्तों को डोर को मजबूत रखने का श्रेष्ठ माध्यम हैं।
“संयुक्त परिवार की आत्मा—प्रेम, त्याग और उत्तरदायित्व, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। यदि ये मूल्य बनाए रखें, तो भारत का परिवारिक ताना-बाना हमेशा उन्नत और स्वस्थ रहेगा।”

ओखला डिपो में लगभग 101 चालकों का दिल्ली परिवहन निगम के मैनेजर और स्विच मोबिलिटी के मैनेजर द्वारा शोषण घटने का नाम नहीं ले रहा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम के द्वारा स्विच मोबिलिटी के ओखला डिपो में लगभग 101 चालकों का दिल्ली परिवहन निगम के मैनेजर और स्विच मोबिलिटी के मैनेजर द्वारा शोषण घटने का नाम नहीं ले रहा, मामले की ताजा जानकारी के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम के कंटेन्ट कर्मचारियों को स्विच मोबिलिटी के मैनेजर और दिल्ली परिवहन निगम ओखला डिपो के मैनेजर पर भ्रष्टाचार और मिलीभगत का आरोप लगाते हुए एवं प्राइवेट कंपनी स्विच मोबिलिटी के द्वारा जबरदस्ती ओके ड्यूटी का दबाव देना प्राइवेट कंपनी के मैनेजर को भारी पड़ा लगभग 40 कर्मचारियों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा देने का फैसला किया जिस इस्तीफे को दिल्ली परिवहन निगम के ओखला डिपो मैनेजर ने नामंजूर कर दिया, अभी कुछ दिनों पहले ओखला डिपो के मैनेजर ओके ड्यूटी के दबाव की वीडियो वायरल होने के बाद कर्मचारियों का कहना है कि वह 8:30 घंटे ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं, डिम के अधिकारी मानने को तैयार नहीं और अपनी ड्यूटी सभी शर्तों पर ओके करने के कारण कर्मचारियों ने कहा कि हम किसी भी प्रकार पब्लिक की जान और माल का नुकसान नहीं करेंगे जिस कारण कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 10 महिला ड्राइवर का तबादला 5 को नोएडा डिपो और 5 को राजघाट डिपो में किया गया, इन सभी कर्मचारियों ने समान काम की समान वेतन की मांग, और रोजगार की सुनिश्चितता को लेकर दिल्ली परिवहन निगम के MD सचिन सिंघे को भी पत्र लिखा।

S.No.	NAME (SURNM)	Design	T.NO.	FROM	TO	Contact No.
1	MAITA DEVI	Cont. Driver	123550	OKD M/s Switch Mobility	NOIDA	989962302
2	ANITA KUMARI	Cont. Driver	123522	OKD M/s Switch Mobility	RJD-1	8742506970
3	DIPTI	Cont. Driver	123507	OKD M/s Switch Mobility	NOIDA	7019735550
4	HEMLATA	Cont. Driver	123713	OKD M/s Switch Mobility	NOIDA	9873579763
5	SHAYASHRI	Cont. Driver	123615	OKD M/s Switch Mobility	RJD-1	8749599144
6	LATA RATHOUR	Cont. Driver	123554	OKD M/s Switch Mobility	NOIDA	9826509476
7	BUDHA KANTI	Cont. Driver	123534	OKD M/s Switch Mobility	NOIDA	9854678646
8	SATYAWATI	Cont. Driver	122617	OKD M/s Switch Mobility	RJD-1	8851894097
9	REKHA	Cont. Driver	123565	OKD M/s Switch Mobility	RJD-1	8743955322
10	ASHU SATTAR	Cont. Driver	123601	OKD M/s Switch Mobility	RJD-1	9826918332
11	DEVI CHAND	Cont. Driver	70127	OKD	OKD M/s Switch Mobility	9050368292
12	JOGINDER SINGH	Cont. Driver	70293	OKD	OKD M/s Switch Mobility	7678245996
13	MAHESH KUMAR	Cont. Driver	70297	OKD	OKD M/s Switch Mobility	9099618472
14	RAKESH KUMAR SHARMA	Cont. Driver	70341	OKD	OKD M/s Switch Mobility	9818750976
15	PRESH PAL	Cont. Driver	70554	OKD	OKD M/s Switch Mobility	8910533021
16	KUNWAR PAL	Cont. Driver	70933	OKD	OKD M/s Switch Mobility	9628350108
17	PARMOD KUMAR	Cont. Driver	70968	OKD	OKD M/s Switch Mobility	9810247210
18	JANAK SINGH	Cont. Driver	70979	OKD	OKD M/s Switch Mobility	9911998750
19	ASHOK KUMAR	CONT DRIVER	71370	OKD	OKD M/s Switch Mobility	8700291041

20	DAVENDRA KUMAR CHAUHAN	CONT DRIVER	71461	OKD	OKD M/s Switch Mobility	9873655505
<p>परिवहन विभाग के अधिकारियों को सूचित करने के लिए निम्नलिखित सूची में उल्लिखित चालकों को सूचित किया जा रहा है कि वे अपने वर्तमान कार्यस्थल पर उपस्थित रहें और अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहें।</p> <p>परिवहन विभाग के अधिकारियों को सूचित करने के लिए निम्नलिखित सूची में उल्लिखित चालकों को सूचित किया जा रहा है कि वे अपने वर्तमान कार्यस्थल पर उपस्थित रहें और अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहें।</p> <p>परिवहन विभाग के अधिकारियों को सूचित करने के लिए निम्नलिखित सूची में उल्लिखित चालकों को सूचित किया जा रहा है कि वे अपने वर्तमान कार्यस्थल पर उपस्थित रहें और अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहें।</p>						

टेंपल ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
 Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlhasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम - डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर टीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए - 4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
 कॉर्पोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

चतुर्दशी का श्राद्ध आज



दिया जाता है।

चतुर्दशी श्राद्ध कैसे करें ?

=====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

की कामना करें।

* श्राद्ध करने वाले जातक पहले स्वयं स्नान करके शुद्ध हो जाएं, उसके बाद श्राद्ध कर्म करने वाले स्थान को भी शुद्ध कर लें।

* कुश, जल, तिल, गंगाजल, दूध, घी, शहद की जलांजलि देने के बाद दीपक, अगरबत्ती, धूप जलाएं।

* श्राद्ध से पहले पितरों का स्मरण करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

* तिल के पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किए जाते हैं।

* अब पितरों की पसंद का भोजन

बनाकर उसमें से गाय, कौवा, चींटी, कुत्ते जैसे जीवों के लिए एक-एक अंश निकालें।

* इस दौरान पितरों का आह्वान कर उनसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना करें।

* इसके बाद ब्राह्मण को भी भोजन कराएं। श्राद्ध के अवसर पर यदि दामाद, भतीजा या भांजा भी भोजन करें, तो इससे पितृ विशेष प्रसन्न होते हैं।

चतुर्दशी श्राद्ध का महत्व

=====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

====

मृत्यु का मतलब है कि किसी की मृत्यु हल्ला, आत्महत्या, दुर्घटना, या किसी और वजह से हुई हो। जिन लोगों की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई हो, उनका श्राद्ध सर्वपितृ अभावस्था को करना चाहिए।

चतुर्दशी के दिन श्राद्ध करते समय अंगुली में दरभा घास की अंगुठी पहनी जाती है। चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और यमदेव की पूजा की जाती है। चतुर्दशी के दिन तर्पण और पिंडदान करने के बाद गरीबों को दान किया जाता है। ज्योतिषों के मुताबिक, चतुर्दशी के दिन दोपहर में कुतुप मुहूर्त में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए।

श्रद्धा का मान हो..।



वह हमारे पितृ, हमारे लिए सब कुछ हैं, उनकी आशाओं पर हम सटीक बैठें यही अभिलाषा है हम सभी की, श्राद्ध दिन में श्रद्धा का मान हो...।

उनका दुनिया से चले जाना, पर दुनिया में उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना हमारा फर्ज है हमारा धर्म है, श्राद्ध दिन में श्रद्धा का मान हो...।

वो भूखे नहीं रहें, उनका मन तुल्य हो, उनके आशीर्वाद से हम खुश रहें हमारे पूर्वज हमारे लिए पुण्य के पुष्प हैं, श्राद्ध दिन में श्रद्धा का मान हो...।

वह राह नहीं भटकें, इसके लिए, हम ऐसी रोशनी प्रफुल्लित करें पुण्य के उदयमान सूरज बनें, श्राद्ध दिन में श्रद्धा का मान हो...।

वह हमारे पितृ देवता हमारे सब कुछ, उन्हें नाराज ना हम करें वह हमारे पथ प्रदर्शक स्वाभिमान हैं श्राद्ध दिन में श्रद्धा का मान हम करें...।।

प्रेषक
स्वरचित रचना
रचनाकार हरिहर सिंह चौहान जबरी बाग
नरिया इन्दौर

गौरी शंकर प्रिया जी ने नवरात्र पर विशेष चर्चा की

हृदयेश कुमार की रिपोर्ट

बिहार के जमुई खैरा में जन्मी गौरी शंकर प्रिया ने विशेष शिक्षा श्री चन्द्रावन धाम से लेकर अपने जीवन को समाजहित में समर्पित करते हुए हिंदू धर्म प्रचार प्रसार करते हुए श्री मद भागवत कथा वाचिका हैं जिनको सिंगापुर और भारत सरकार द्वारा भी सम्मान मिल चुका है हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि

जमुई खैरा के शिव मंदिर परिसर में संगोष्ठी का आयोजन कर बताया कि नवरात्र एक हिन्दू पर्व है जिसमें नौ रातें देवी दुर्गा और उनके नौ अवतारों की पूजा की जाती है। यह संस्कृत शब्द 'नव' (नौ) और 'रात्र' (रात) से बना है, जो देवी शक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह पर्व भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है, जैसे गुजरात में गरबा और डांडिया, और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा। शक्ति की पूजा: नवरात्र शक्ति की देवी, दुर्गा की उपासना का त्योहार है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।

श्री मद भागवत कथा करवाने के लिए 9534459277 , 8920446101 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं

आध्यात्मिक श्रद्धा: यह नौ दिन शरीर, मन और बुद्धि को शुद्ध करके देते हैं, जिससे अकाल दूर होती है और आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है।

प्रकृति और चेतना का उत्सव: यह त्योहार प्रकृति के साथ चेतना के तात्त्विक को भी दर्शाता है, जहाँ प्रत्येक दिन तीन गुणों (तम, रज, सत्व) की आराधना की जाती है।

प्रमुख उत्सव और रीति-रिवाज
शारदीय नवरात्र: यह सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध नवरात्र है, जो आश्विन (क्वार) महीने में

मनाई जाती है और दशहरा के दिन इसका समापन होता है।

चैत्र नवरात्र: हिन्दू कैलेंडर के अनुसार साल की शुरुआत चैत्र महीने में नौ दिनों के लिए चैत्र नवरात्र के रूप में होती है।

नवरात्रि उपवास का अर्थ है नौ दिनों तक मां दुर्गा की पूजा करना और कुछ खास नियमों का पालन करना, जिसमें मांसाहारी भोजन, प्याज, लहसुन, दाल और अनाज से परहेज किया नमक और दूध का सेवन न करना और दूध का सेवन न करना और नकारात्मक आदतों से दूर रहना भी महत्वपूर्ण है।

फलाहार: फल, फल और सब्जियों का सेवन करें।

सात्विक भोजन: फलाहार के साथ, आप सेंधा नमक डालकर बनी खीर, हलवा, या साबूदाना की खिचड़ी खा सकते हैं।

दूध और जल: दूध और जल का सेवन भी उपवास में किया जाता है।

अन्य: नींबू का रस, मेवे, दही, और दही से बने पदार्थ भी खाए जा सकते हैं।

क्या न खाएं:

मांसाहार: मांस, मछली, अंडे और किसी भी प्रकार के नोन-वेज आइटम का सेवन बर्जित है।

मसालेदार और तामसिक भोजन: प्याज और लहसुन को छोड़ दें, मसालेदार भोजन, दाल और

अनाज का सेवन भी नहीं करना चाहिए।

नशा: शराब और तंबाकू का सेवन पूरी तरह से वर्जित है।

प्रसंस्कृत भोजन: पैकेट वाले और प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए।

ब्रह्मचर्य: उपवास के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें।

मन की पवित्रता: मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए और किसी को देस जाता है। उपवास के दौरान सात्विक

पहुँचाने वाले वचन नहीं बोलने चाहिए।

शा री र क स्वच्छता: स्वच्छता और सात्विकता बनाए रखना जरूरी है।

नकारात्मकता से बचे: क्रोध, लोभ और अन्य नकारात्मक विचारों से दूर रहें।

उपवास का पालन: उपवास को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप त्रक पाएंगे तो नौ कन्याओं को भोजन कराकर

दक्षिणा देनी चाहिए

भक्त उपवास, प्रार्थना और विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से देवी की शक्ति, बुद्धि और समृद्धि के लिए आराधना करते हैं।

देवी के नौ रूप: नवरात्रि के प्रत्येक दिन देवी के एक विशेष अवतार की पूजा की जाती है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा आदि।

विजयदशमी: दसवें दिन विजयदशमी के रूप में अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है,



जब हम मन की अपरिमित शक्ति को किसी विशेष लक्ष्य की ओर लगा देते हैं और साथ ही लक्ष्य को भ्रष्ट करने वाली वृत्तियों पर अंकुश भी लगा लेते हैं, तो वही मन की शक्ति जीवन को विजयी/सफल बना देती हैं।



ध्यान रहे कि धनुष से छूटा बाण अपनी सीध में ही चलता जाता है, वह आस-पास की किसी वस्तु के साथ अपना संपर्क न रख कर, सीधा वही पहुँचता है जो कि उसके सामने होता है। अर्थात् सामने की तरफ ही उसकी आँख खुली रहती है और सब ओर से बन्द। इसलिये जो लोग लक्ष्य की तरफ आँख रखकर, शेष सभी ओर से अपनी इन्द्रियों को मोड़ लेते हैं और लक्ष्य की ओर ही समस्त शक्ति लगा देते हैं वह ही सफल होते हैं। जिस प्रकार अर्जुन से पूछे गये द्रोण के प्रश्न में, अर्जुन के लक्ष्य के रूप में, उसकी अन्तरात्मा में एक ही ध्वनि/एक ही दृश्य (मछली की आँख) गूँजता है। अतः उसे अपना लक्ष्य ही महत्वपूर्ण दिखाई देता है। वास्तव में बाण की तरह, हमारा अपने लक्ष्य के प्रति तन्मयता का होना श्रेयस्कर है।

जलियांवाला बाग हत्याकांड...!

ब्रिटिश सरकार के रॉलेट एक्ट का विरोध, हमारे अधिकारों में कटौती आया था क्रोध। गाँधी जी की गिरफ्तारी का क्रिया है विरोध, जलियांवाला बाग की सभा आया अवरोध।

13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुई ये घटना, ये सपनों का ऐसे आयोजित सभा में डटना। निहत्थे भारतीयों पर ब्रिटिश सैनिक टूट पड़े, बच्चे, बूढ़े, जवान गोलियाँ सीने पे खाते खड़े।

जिसमें सैकड़ों मारे गए और हजारों घायल, सारा देश हुआ 'नतमस्तक' हम डर कायल। 'स्वतंत्रता संग्राम' में हुआ एक नया सूत्रपात, ब्रिटिशों के प्रति आक्रोश पनप हुए आघात।

संजय एम तराणेकर

पाञ्चजन्य

दक्षिणावर्ती, गुलाबी रंग और संगीतमय गंधीर घोष वाला एक शंख!

कौन अभाग्य हिंदू होगा जो इस धर्मघोषक के बारे में न जानता होगा! कौन ऐसा हिंदू होगा जो इससे निःसृत पुण्यध्वनि को न जानता होगा जो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता की पूर्वभूमिका बनी!

कौन ऐसा जड़ हिंदू होगा जो इसके स्वामी कृष्ण को न जानता होगा!

डॉ. लॉजिस्टिक्स : युवाओं को व्यावहारिक अनुभव से गढ़ रहा है भारत का भविष्य सप्लाई चेन प्रोफेशनल

लेखक: डॉ. अंकुर शरण

भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स वह रीढ़ है जो उद्योगों, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जोड़ती है। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि इस क्षेत्र में युवा केवल किताबों और सिद्धांतों तक ही सीमित रह जाते हैं, जबकि जमीनी अनुभव ही असली दक्षता और विशेषज्ञता देता है।

इसी अंतर को पाटने का प्रयास है डॉ. लॉजिस्टिक्स पहल का। इसका उद्देश्य है कि छात्रों और युवा पेशेवरों को मीडिया, कार्यशालाओं और सीधे उद्योग जगत से जोड़कर व्यावहारिक अनुभव दिलाया जाए। यहाँ न केवल किताबों का ज्ञान मिलता है, बल्कि कंटेनर डिपो, बंदरगाह, ट्रांसपोर्ट हब और सप्लाई चेन के विभिन्न चरणों का प्रत्यक्ष अनुभव भी करवाया जाता है।

आज हम मिलते हैं श्री मनीष सहाय से, जो लामागो दशक से ICD EXIM ऑपरेशन्स की अगुवाई कर रहे हैं। वे कहते हैं कि लॉजिस्टिक्स में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है —

धैर्य और सूक्ष्मता से काम करना —



क्योंकि हर दस्तावेज, हर प्रक्रिया की अपनी समयसीमा और महत्व है।

संचार और टीमवर्क — जहाज, ट्रक, रेल और वेयरहाउस सब आपस में जुड़े हैं, और एक छोटी सी कमी पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकती है।

तकनीक को अपनाना — आज डिजिटल

प्लेटफॉर्म, ट्रैकिंग सिस्टम और ऑटोमेशन के बिना अंतरराष्ट्रीय व्यापार संभव ही नहीं।

वैश्विक सोच और स्थानीय कार्यप्रणाली — लॉजिस्टिक्स एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, पर देश-भारतीय जरूरतों और चुनौतियों के हिसाब से ढालना ही असली दक्षता है।

डॉ. लॉजिस्टिक्स की यही कोशिश है कि

मनीष सहाय जैसे अनुभवी पेशेवरों के अनुभव को युवाओं तक पहुँचाया जाए। ताकि आने वाले वर्षों में भारत के पास केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि वास्तविक कौशल से लैस लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल्स हों, जो देश की विश्वव्यापी बनने की दिशा में आगे बढ़ा सकें।

लाल किला मैदान पर आर्य बम्बर के साथ करेंगी लाइव परफॉर्मेंस

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। देश की सबसे लोकप्रिय लव कुश रामलीला इस वर्ष खास होने जा रही है। फिल्म और टीवी जगत की चर्चित अदाकारा पूनम पांडे महाबली रावण की पत्नी मंदोदरी का दमदार किरदार निभाएंगी। लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि — “जब हमने इस भूमिका के लिए पूनम पांडे से संपर्क किया तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का सपना है जो प्रभु श्रीराम की कृपा से पूरा हुआ है। लाइव मंचन में हजारों दर्शकों के सामने मंदोदरी की साकार करना चुनौतीपूर्ण है, इसलिए वह अभी से गहन रिहर्सल कर रही हैं।” पूनम पांडे ने कर्मा द जर्नी, जोएसटी: गलती से सिर्फ, जैसी फिल्मों और टीवी धारावाहिक सीआईडी में अपनी पहचान बनाई है। मंच पर वह प्रसिद्ध अभिनेता आर्य बम्बर के साथ नजर आएंगी, जो इस वर्ष रावण की भूमिका निभा रहे हैं। लाल किला मैदान में आयोजित लव कुश रामलीला का भव्य मंचन 22 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक होगा, जबकि 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा।

एआरआईएसई स्कूल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2025 परंपरा, प्रौद्योगिकी और सहानुभूति के मिश्रण का अन्वेषण करता है

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली: एसोसिएशन फॉर रीइन्वेंटिंग स्कूल एजुकेशन (ARISE), भारत का एकमात्र उद्योग चैंबर निकाय जो केवल स्कूल शिक्षा क्षेत्र पर केंद्रित है, ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) — भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा शीर्ष व्यवसाय संगठन — के सहयोग से वार्षिक स्कूल शिक्षा सम्मेलन 2025 को 11-13 सितम्बर, 2025 तक सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस सम्मेलन ने शिक्षकों, नीति निर्माताओं, विचार नेताओं और नवोन्मेषकों को एक साथ लाकर भारत की K-12 शिक्षा के भविष्य की पुनर्कल्पना की।

“द न्यू बैलेंस: रीइंजिन एंड टेक्नोलॉजी, एम्पावर्ड बाय एम्प्लॉयी” विषय पर आधारित इस सम्मेलन में इमर्सिव स्कूल टूर, विषयगत मास्टरक्लास, विचारोत्तेजक मुख्य भाषण सत्र, शिक्षा केंद्रित सार्वजनिक नीति संवाद और विषय-वस्तु संबंधित चर्चाएँ शामिल थीं, जिनमें यह संबंधित किया गया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और नवाचार द्वारा आकार लिए विश्व में शिक्षा की भूमिका कैसे विकसित हो रही है। सम्मेलन का उद्घाटन आशीष सूद, माननीय शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा किया गया

विचार नेताओं में आरटी माननीय लॉर्ड जिम नाइट, पूर्व यूके स्कूल मंत्री एवं को-फाउंडर इंस्ट्रक्शनल कोचिंग ग्रुप तथा रिचर्ड कुलाटा, अमेरिका के शिक्षा विभाग में शिक्षक प्रौद्योगिकी कार्यालय के पूर्व कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन ने वैश्विक दृष्टिकोण साझा किए। वहीं भारत के प्रख्यात लेखक गुरुंजन दास, नीति निर्माता एवं प्रभावशाली व्यक्ति और शिक्षा उद्योगियों ने भी अपने विचार साझा किए जो सम्मेलन की थीम के साथ जुड़े।

तीन-दिवसीय सम्मेलन ने 500 से अधिक प्रतिनिधियों—प्रधानाचार्यों, स्कूल संस्थापकों, एडटेक नवोन्मेषकों, नीति निर्माताओं और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों—को एकत्रित किया, जिन्होंने मास्टरक्लास में भाग लिया। इन सत्रों में विषय शामिल थे जैसे किशोरों के लिए मस्तिष्क कौशल, छात्रमानसिक कल्याण, तकनीक अपनाने में नेतृत्व, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDPA), नई उम्र का इन्फ्रस्ट्रक्चर डिजाइन और पैमल चर्चाएँ जिन्होंने इस बात पर विचार किया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने और बच्चे की प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को सुरक्षित रखने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

एनडीएमसी ने सेवा पर्व के अंतर्गत “विकसित भारत के रंग, कला के संग” विषय पर एक विशाल कला-महोत्सव का आयोजन किया

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने सेवा पर्व के अंतर्गत “विकसित भारत के रंग, कला के संग” विषय पर एक विशाल कला महोत्सव कार्यक्रम में एक साथ 35,000 से ज्यादा कलाकारों और छात्रों द्वारा 10 किलोमीटर लंबी लाइव कैनवास पेंटिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह कार्यक्रम एनडीएमसी द्वारा त्रिवेणी कला संगम और दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ लॉन में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री - किरन रिजजू ने कहा कि आज का कर्तव्य पथ कल्पना से परे था, जहाँ हजारों युवा एक साथ मिलकर 10 किलोमीटर लंबे कैनवास पर विकसित भारत के रंग उकेरने आए। सभी कलाकारों और छात्रों का उत्साह अद्भुत था और वे अपने सपनों के विकसित भारत को चित्रित करते कदम नहीं रहे थे। कला के प्रति एनडीएमसी की इस अद्भुत पहल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पर्व के दौरान युवाओं का यह एक अनूठा कला महोत्सव है।

अपने संबोधन में, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री - गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह आयोजन रचनात्मक कला का एक ऐतिहासिक क्षण है, जहाँ हजारों युवाओं ने एक साथ 10

किलोमीटर लंबे कैनवास पर रंग भरकर अपने सपनों के भारत की कल्पना की है। युवाओं में रचनात्मकता की भावना यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सेवा पर्व के दौरान आयोजित किया जा रहा है।

भारत के माननीय केंद्रीय रेल मंत्री - अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेवा पर्व के अंतर्गत “विकसित भारत के रंग, कला के संग” का आयोजन केवल दिल्ली में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में - प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले और प्रत्येक गाँव में किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे भारत से 35,000 से अधिक कलाकारों की एक मंच पर सफल भागीदारी एकता का प्रतीक है और माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मनाए जा रहे सेवा पर्व को वास्तव में यादगार बनाने के लिए एक ऐतिहासिक उत्सव है।

माननीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री - ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस भव्य आयोजन के लिए टीम एनडीएमसी के प्रयासों की सराहना की, जहाँ पूरे भारत के कलाकार अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा का इतनी खूबसूरती से प्रदर्शन करने के लिए एक मंच पर एकत्रित हुए।

इस अवसर पर, दिल्ली की मुख्यमंत्री - रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है, जहाँ देश भर के



विभिन्न राज्यों से आए हजारों नामचीन कलाकारों और छात्रों ने मिलकर 10 किलोमीटर लंबे कैनवास पर चित्रकारी की है। आज राजधानी में, विभिन्न युवाओं के विचारों और सपनों को विविध रंगों के साथ कैनवास पर उकेरा गया है, जो एक अद्भुत रचनात्मक संगम का प्रतीक है। यह कला उत्सव माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पर्व का एक हिस्सा है, जो हमें हमारे कर्तव्यों को याद दिलाता है और उन्हें जिम्मेदारी के साथ निभाने की प्रेरणा भी देता है। अगर हम सब मिलकर एक-एक करके अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तभी हम अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बना पाएँगे। उन्होंने कहा कि सेवा पर्व के तहत एनडीएमसी की ओर से मोदी जी को यह कलात्मक उपहार, बेहद खास है।

इस अवसर पर, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष - कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि माननीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में - सेवा ही संकल्प है, भारत प्रथम प्रेरणा है - एनडीएमसी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 तक सेवा पर्व के अंतर्गत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत, त्रिवेणी कला संगम और दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से आज विकसित भारत के रंग, कला के संगर नामक भव्य कला कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

चहल ने यह भी बताया कि आज एक ऐतिहासिक दिन है जब लाइव पेंटिंग के सभी पिछले रिकॉर्ड टूट गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर्व में हर राज्य, हर जिले और हर गाँव की भागीदारी देखी गई है। हर एक रिकॉर्ड में एक साथ सबसे अधिक कलाकारों के योगदान का रिकॉर्ड 5,084 कलाकारों का था, जो 2014 में पनामा में फंडासिओन ओल्गा सिंक्लेयर द्वारा पनामा नहर की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बनाई गई एक पेंटिंग के लिए बनाया गया था। आज एनडीएमसी ने इस रिकॉर्ड को परा करके नई दिल्ली के कर्तव्य पथ स्थित लॉन में 35,000 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा 10 किलोमीटर लंबी लाइव कैनवास पेंटिंग बनाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है।

राज्यसभा सांसद से समाज सेवक एवं युवा मोर्चा मंत्री ईशु पर्वा की सौजन्य भेंट

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। आदरणीय राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नगर जी से समाज सेवक एवं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंत्री ईशु पर्वा जी ने सौजन्य भेंट की। यह मुलाकात समाज के हितों और जनता की समस्याओं पर केंद्रित रही।

बैठक के दौरान ईशु पर्वा जी ने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और समाज कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने आम जनता की आवाज को सांसद जी तक पहुँचाते हुए ठोस समाधान के लिए सुझाव दिए।

माननीय सुरेंद्र सिंह नगर जी ने समाज के प्रति ईशु पर्वा जी की सक्रिय भूमिका की सराहना की और कहा कि जनता के कल्याण के लिए सकारात्मक पहलें निरंतर जारी रहेंगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि समाज के विकास और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

यह मुलाकात समाज सेवा और जनहित के कार्यों को नई दिशा देने वाली साबित हो रही है।



महेंद्रा पार्क में युवक पर चलायी थी गोलियां। आरोपी जान से मारने की दे रहे हैं धमकियां

नई दिल्ली (संवाददाता) : उत्तरी पश्चिमी जिले के महेंद्रा पार्क इलाके में 7 अगस्त को दो दोस्त के साथ नारथीट वाले पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। जानकारी के अनुसार नाथिक अर्क काकू दूसरा निरिक्षित सक्सेना, महेंद्रा पार्क में वाइलीन खाने जा रहे थे। तीन लोग एक साथ आते। दोनों दोस्तों को नाथिक और उनके दोस्त को पीटा शुरू कर देते हैं। किसी तरह से दोनों युवक मौके से जान बचाकर भाग जाते हैं। आरोपी अपने साथियों के साथ पीछा करते हुए, जलंधरपुरी के DDA फ्लैट यंत्राजी कैम्प में एक दरवाह के पास पहुँचते हैं। आरोपी ने पीड़ित पर गोलियां चला दी। गनीमत रही गोलियों की लगी नहीं। गोलियों दिवार और जमीन पर जाकर लगी। किसी तरह पीड़ित युवक मौके पर अपनी जान बचाकर भाग गए थे। बताया जाता है कि पीड़ित नाथिक के साथ आरोपियों की पुरानी रीति है। 2022 में पीड़ित नाथिक के साथ कुछ लड़कों ने झगड़ा कर नारथीट करी थी। इसकी शिकायत भी पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई थी। बताया जाता है कि पीड़ित पर तीन गोलियां चलायी गई थी। आरोपी पीड़ित नाथिक और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं बताया जाता है कि आरोपी जलंधरपुरी DDA फ्लैट का रखे वाला है और उस पर पहले से तीन गोलियां दर्ज हैं। नाथिक ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है कि उसकी और उसके परिवार की रक्षा करी जाए, नाथिक और उनका परिवार उरा सक्सेना हूया है। उन्होंने थाना अध्यक्ष से लेकर पुलिस आयुक्त को लिखित में शिकायत दी है। फ़िरतखत पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई।



अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के साथियों का मान सम्मान करना और उनके साथ स्नेह पूर्ण आत्मीय संबंध बनाये रखना अभिनेता गायक उतर पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद एवं भाजपा दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री मनोज तिवारी जी की विशेषता है। कल रात्रि को मनोज जी के निवास स्थान पर उनके कार्यकाल के समय के हम तीनों महामंत्रियों भाई रविंद्र गुप्ता पूर्व महापौर, भाई कुलजीत चाहल वर्तमान में वाईस चेयरमैन NDMC, और मैंने सुखदेव समय बिताया एवं स्वादिष्ट भोजन किया। राजेश भाटिया पूर्व महामंत्री भाजपा दिल्ली प्रदेश एवं डिप्टी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी नार्थ MCD।



रक्षा गरबा-डांडिया और दुर्गा पूजा महोत्सव

स्टॉल प्रस्ताव:

सिंगल साइड ओपन स्टोल : 2000

कॉर्नर साइड स्टोल : 3500

तीन साइड ओपन स्टोल : 4500

सिर्फ एक टेबल : 1000

सिर्फ दो टेबल : 1250

कार्यक्रम विवरण:

रक्षा गरबा-डांडिया और दुर्गा पूजा महोत्सव

स्थान : डीडीए ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड के सामने, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बगल में, PNB बैंक के पीछे, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075

तारीखें: 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025

* दुकान का आकार : 10 फीट x 10 फीट

* शामिल सुविधाएँ:

* 2 कुर्सियाँ * 2 टेबल

* लाइट व चार्जिंग प्वाइंट

भुगतान की शर्तें:

* अग्रिम भुगतान आवश्यक

* बुकिंग के समय 50% भुगतान

* कब्जे के समय 50% भुगतान

संपर्क : इंदु राजपूत

मोबाइल : 9210210071

विशेष सूचना

नवरात्रि में मातारानी की खंडित मूर्तियाँ, टूटे हुए फोटो, पुरानी चुनरियाँ

और नवरात्रि में बोध गए जवारों का विसर्जन

● दशहर के दूसरे दिन

● दिनांक : 3 अक्टूबर की सुबह

● स्थान : रक्षा नवरात्रि गरबा एवं दुर्गा पूजा ग्राउंड

स्थान विवरण:

रामलीला मैदान के सामने,

आरटीओ अथॉरिटी के पास,

सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली

संपर्क सूत्र : इंदु राजपूत, मोबाइल : 9210210071

सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस पावन विसर्जन में सहभागी बनें।

रक्षा द सेवियर एवं टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत) की ओर से

गरबा महोत्सव में विशेष अपील

हमारी रक्षा द सेवियर एवं टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर

एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत) की ओर से रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा

महोत्सव में आने वाले सभी लोगों से विनम्र निवेदन है—

इस नवरात्रि एक सेवा झाड़व चलाई जा रही है

आप अपने घर से लाएँ और दान करें:

● पुराने कपड़े

● पुराने कंबल

● पुराने जूते-चप्पल

● बच्चों के लिए बैग

● किताबें

आपका छोटा-सा योगदान किसी ज़रूरतमंद के जीवन में बड़ा बदलाव

ला सकता है

स्थान : रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव

रामलीला मैदान के सामने, आरटीओ अथॉरिटी के पास

सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली

इंदु राजपूत – 9210210071,

अभिषेक राजपूत 83928 02013,

पिंकी कुंड़ 7053533169

हरगांव शुगर मिल प्रबंधन ने मजदूरों से एक झटके में छीन लिया रोजी-रोटी का सहारा, जिम्मेदार खामोश

सुनील बाजपेई

कानपुर। इस देश में अगर कोई सर्वाधिक शोषण का शिकार है तो वह असंगठित क्षेत्र के मजदूर ही हैं। जब भी इच्छा होती है मालिकान और प्रबंधन उनकी रोजी-रोटी का सहारा एक झटके में छीन लेते हैं। मजदूरों के इस तरह के अमानवीय शोषण के पक्ष में जिम्मेदार लोग भी सर्वप्रधान एवं मालिकानों के पक्ष में ही खड़े नजर आते हैं, यही कारण है कि लगातार गुहार लगाने के बाद भी लिखित शिकायत करने के बाद भी उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती, जिसकी वजह से ही यह सभी गरीब मजदूर घुट घुट कर जीने और मरने को भी मजबूर होते हैं।

कुछ इसी तरह के अमानवीय हालातों के शिकार लगभग एक सैकड़ा से भी ज्यादा बताए जाने वाले वह भी मजदूर हैं, जिनकी सेवाएं जबर्न समाप्त कर दी गईं, इनमें से कई ऐसे अभाग्य मजदूर भी हैं, जो सरकार से सहायता का इंतजार करते-करते असमय मौत का भी शिकार हो गए। शोषण और उत्पीड़न अन्याय की पराकाष्ठा वाला यह मामला अवध शुगर मिल लि.हरगांव सीतापुर का है।

मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय की पराकाष्ठा पर

घोर चिन्ता व्यक्त करते हुए शोषितों, बंचितों और किसी भी तरह के अन्याय तथा उत्पीड़न के शिकार लोगों की हर संभव सहायता के साथ ही उन्हें न्याय दिलाने में भी अग्रणी तेजतरंग और व्यवहार कुशल हाई कोर्ट के अधिवक्ता तथा हिन्द मजदूर सभा के भी प्रदेश सचिव, अविनाश पाण्डेय ने यहां बताया कि इस मिल में काम करने वाले 100 से अधिक कर्मचारियों की सेवाएं जबर्न समाप्त कर दी गयी हैं। जिनमें से शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति के इंतजार में अब तक कई मजदूरों की मौत भी हो चुकी है।

हिन्द मजदूर सभा के प्रदेश सचिव कानून विद हाईकोर्ट के अधिवक्ता अविनाश पाण्डेय के मुताबिक भविष्यनिधि कार्यालय में 7ए की कार्यवाही चल रही है। वहां भी मालिकों व मिल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शम दाम दण्ड भेद करके मजदूरों के शोषण में लगे हैं। इस अमानवीय शोषण और उत्पीड़न को अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके किसी भी बकाए का भुगतान किए बगैर ही उनसे जबर्न आवास भी खाली कराये जा रहे हैं। इसके लिए कर्मचारियों उमाशंकर पाल, राम तुलारे, राम सनेही, अशोक कुमार, सुमन, राम कुमार यादव, अनिल



श्रीवास्तव विन्दा प्रसाद आदि की बिजली, पानी काट कर बेधर करने का भी कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश कर्मचारी बहुत दूर जा रहा क्षेत्रों के मूल निवासी हैं। चूँकि भविष्य में 7 ए ही कार्यवाही चल रही है। इसलिए वह वापस भी नहीं जा सकते।

हाई कोर्ट के जाने माने वकील और हिन्द मजदूर सभा के प्रदेश सचिव, अविनाश पाण्डेय ने यहां बताया कि इनके निकाले जाने का वाद सरकार द्वारा

अभिनिर्णय हेतु श्रम न्यायालय में भेज दिया गया है, जिससे नाराज होकर मालिकान उन्हें बेधर करने जैसी यह कार्यवाही कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इस अन्याय अत्याचार और शोषण की लगातार लिखित शिकायत किए जाने के बाद भी अपर श्रमायुक्त और सहायक श्रमायुक्त सीतापुर द्वारा भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जबकि उन्हें इस सम्बन्ध में स्थगन दिये जाने हेतु

तमाम प्रार्थना पत्र, अभिलेख और कई कार्यस्थलों के आदेश भी निर्गत किये गये।

हिन्द मजदूर सभा के प्रदेश सचिव और पीड़ितों की आवाज बुलंद करने में भी अग्रणी उच्च न्यायालय के वकील अविनाश पांडेय ने यह भी बताया कि जिम्मेदार अधिकारियों के इस रवैये के खिलाफ कर्मचारियों में हताशा, निराशा व उत्तेजना का माहौल है। क्योंकि प्रबंधन के इस अमानवीय आचरण से

दौलत और समाज का नज़रिया

डॉ. मुस्ताक अहमद शाह

जब ईसान के पास पैसा होता है तो उसकी हर बात को लोग बहुत अहम मानने लगते हैं, वही बातें जो पहले लोगों को बेकार या फ़ालतू लगती थीं, दौलत आने के बाद हिकमत और तजुबों की तरह समझी जाती हैं, असलियत यह है कि पैसा ईसान का चरित्र और नीयत नहीं बदलता बल्कि लोगों का नज़रिया और रवैया बदल देता है, समाज में अक्सर देखा जाता है कि गरीब की राय को कोई अहमियत नहीं दी जाती, उसकी सच्ची बात भी अनसुनी कर दी जाती है लेकिन वही ईसान जब आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाता है तो उसके शब्दों को कीमती सलाह, उसके तौर-तरीके को काबिले तारीफ़ और उसके व्यक्तित्व को रोशन चेहरा कहने लगते हैं, तभी तो कहा गया है — "फ़क्र में सच्चाई दब जाती है, दौलत में झूठ भी सुनहरी लगता है", ईसान की आदत यही है कि वह ताकत और दौलत वालों की तरफ़ खिंचता है, जो ईसान गरीबी में अनदेखा किया जाता है, वही दौलत मिलते ही सम्मान और तवज्जो का हक़दार बन जाता है, इसमें अस्सी मसला पैसे का नहीं बल्कि समाज की सोच का है क्योंकि अमीर के फ़िज़ूल बोल को भी लोग ध्यान से सुनते हैं और गरीब को काम



की सलाह को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, यह भी सच है कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, इसके बिना ईसान की काबिलीयत, शिक्षा और हुनर भी अधूरे लगते हैं, पैसा ही इज़्जत, भरोसे और समाज में स्थान और चरित्र से होती है, मगर समाज ज़्यादातर दौलत का पर्दा आँखों पर डालकर ही फ़ैसला करता है और इसीलिए कहा जाता है कि "आर्थिक तौर पर मजबूत होना सिर्फ़ बेबर नाना नहीं बल्कि लोगों के रवैये का बदल जाना है।"

भागवत निवास में धूमधाम से मनाया गया गोलोकवासी श्रीहरिकृष्ण गुप्ता एवं श्रीमती सूरजमुखी गुप्ता का स्मृति महोत्सव

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। रमणरेती मार्ग स्थित भागवत निवास में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन सम्मान समिति (रिस्पैक्ट एज इंटरनेशनल) के द्वारा पितृ पक्ष के उपलक्ष्य गोलोकवासी श्रीहरिकृष्ण गुप्ता एवं श्रीमती सूरजमुखी गुप्ता का स्मृति महोत्सव अत्यन्त श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम गोलोकवासी श्रीहरिकृष्ण गुप्ता एवं श्रीमती सूरजमुखी गुप्ता के चित्रपत्र का वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य पूजन-अर्चन किया गया। तत्पश्चात ठाकुर गिरिंद्र बिहारी महाराज के समक्ष संतो व भक्तों के द्वारा श्रीहरिनाम संकीर्तन किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन सम्मान समिति (रिस्पैक्ट एज इंटरनेशनल) के संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. गिरीश गुप्ता ने कहा कि भारतीय वैदिक सनातन धर्म में पितृ पक्ष को अत्यन्त पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष दिवंगत पितरों की आत्मा की शांति, तृप्ति और मोक्ष के लिए समर्पित होता है। इन दिनों में पितरों का आशीर्वाद पाने और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए श्राद्ध, पिंड दान



व तर्पण आदि करना चाहिए। प्रख्यात साहित्यकार डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने कहा कि गोलोकवासी हरिकृष्ण गुप्ता और सूरजमुखी गुप्ता अत्यंत भगवत निष्ठ और सेवा भावी विभूति थे। उन्हीं से प्राप्त सद संस्कारों से डॉक्टर गिरीश गुप्ता और उनका पूरा परिवार संत सेवा और लोक कल्याण के कार्यों में संलग्न है। महोत्सव में श्रीमती वीना

गुप्ता, बाबा शुकदेव दास महाराज, सन्त निधि दास महाराज, सन्त जुगल दास, डॉ. राधाकांत शर्मा, राकेश गुप्ता, श्रीमती मधु गुप्ता, दिनेश गुप्ता श्रीमती मंजू गुप्ता आदि की उपस्थिति विशेष रही। महोत्सव का समापन साधु, ब्राह्मण, वैष्णव सेवा एवं वृहद भंडारे के साथ हुआ जिसमें सैकड़ों व्यक्तियों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया।

संजीव कुमार सिंह: एक नया चेहरा, नई उम्मीद - जनता के बीच बढ़ रही संजीव कुमार सिंह की लोकप्रियता

नई दिल्ली। संजय सागर सिंह। बिहार में इस बार की सियासी हवा कुछ अलग है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता ठाकुर संजीव कुमार सिंह एडवोकेट (सुप्रीम कोर्ट) के नेतृत्व में एक नई राजनीतिक ऊर्जा देखने को मिल रही है। वे पूरे राज्य में परिवर्तन की आहट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में जनता किसे अपना विश्वास सौंपती है।

जनता के बीच बढ़ रही है संजीव कुमार सिंह की लोकप्रियता

राष्ट्रीय नेता संजीव कुमार सिंह के समर्थकों के अनुसार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संभावित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार संजीव कुमार सिंह एडवोकेट (सुप्रीम कोर्ट) लगातार बिहार के कोने-कोने में जाकर पंचे बाँट रहे हैं और आम जनता से डोर टूटोर संवाद कर रहे हैं। उन्हें न केवल एक राजनेता बल्कि एक समाजसेवी और जनहित के अधिवक्ता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने वर्षों से गरीब दलित मजदूर जनता को कानूनी सहायता दी है और हर संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े रहे हैं। हाल ही में आई बाढ़ के दौरान उन्होंने पीड़ित गाँवों में पहुँचकर हरसंभव मदद की।

समर्थकों का दावा है कि इस बार बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है और बदलाव का मन बना चुकी है। राज्य के युवा रोजगार की तलाश में हैं और यह भरोसा अब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता संजीव कुमार सिंह पर जाता जा रहा है। उनका कहना है कि बिहार की जनता अब संजीव कुमार सिंह को वोट देकर सत्ता में लाएगी, क्योंकि केवल कांग्रेस के



राष्ट्रीय नेता संजीव कुमार सिंह ही उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सम्मान, और रोजगार की गारंटी दे सकते हैं।

तेजस्वी यादव पर निशाना संजीव कुमार सिंह के समर्थकों ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर कई घोटालों के मामले चल रहे हैं, जिसमें रेलवे घोटाला और जमीन से जुड़ी गड़बड़ियाँ शामिल हैं। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता संजीव कुमार सिंह को ही बिहार की वागडोर संभालनी चाहिए।

संजीव कुमार सिंह: एक नया चेहरा, नई उम्मीद संजीव कुमार सिंह को जनता एक ऐसे नेता के रूप में देख रही है जो रोजगार, दवाई, पढ़ाई, महिला सम्मान और उद्योग जैसे मूलभूत मुद्दों पर काम करना चाहता है। उनके समर्थकों का कहना है कि उनका नाम आज बिहार के बच्चों की जुबान पर है, और वे मजदूर दलित और गरीबों की आवाज बन चुके हैं।

वृन्दावन शोध संस्थान द्वारा प्रियाबल्लभ कुंज में हुआ साँझी संवाद का आयोजन

हरगांव शुगर मिल प्रबंधन ने मजदूरों से एक झटके में छीन लिया रोजी-रोटी का सहारा, जिम्मेदार खामोश

सुनील बाजपेई कानपुर। इस देश में अगर कोई सर्वाधिक शोषण का शिकार है तो वह असंगठित क्षेत्र के मजदूर ही हैं। जब भी इच्छा होती है मालिकान और प्रबंधन उनकी रोजी-रोटी का सहारा एक झटके में छीन लेते हैं। मजदूरों के इस तरह के अमानवीय शोषण के पक्ष में जिम्मेदार लोग भी सर्वप्रधान एवं मालिकानों के पक्ष में ही खड़े नजर आते हैं, यही कारण है कि लगातार गुहार लगाने के बाद भी लिखित शिकायत करने के बाद भी उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती, जिसकी वजह से ही यह सभी गरीब मजदूर घुट घुट कर जीने और मरने को भी मजबूर होते हैं।

कुछ इसी तरह के अमानवीय हालातों के शिकार लगभग एक सैकड़ा से भी ज्यादा बताए जाने वाले वह भी मजदूर हैं, जिनकी सेवाएं

जबर्न समाप्त कर दी गईं, इनमें से कई ऐसे अभाग्य मजदूर भी हैं, जो सरकार से सहायता का इंतजार करते-करते असमय मौत का भी शिकार हो गए। शोषण और उत्पीड़न अन्याय की पराकाष्ठा वाला यह मामला अवध शुगर मिल लि.हरगांव सीतापुर का है।

मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय की पराकाष्ठा पर घोर चिन्ता व्यक्त करते हुए शोषितों, बंचितों और किसी भी तरह के अन्याय तथा उत्पीड़न के शिकार लोगों की हर संभव सहायता के साथ ही उन्हें न्याय दिलाने में भी अग्रणी तेजतरंग और व्यवहार कुशल हाई कोर्ट के अधिवक्ता तथा हिन्द मजदूर सभा के भी प्रदेश सचिव, अविनाश पाण्डेय ने यहां बताया कि इस मिल में काम करने वाले 100 से अधिक कर्मचारियों की सेवाएं जबर्न समाप्त कर दी गयी हैं। जिनमें से शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति के इंतजार में अब तक कई मजदूरों की मौत भी हो चुकी है।

हिन्द मजदूर सभा के प्रदेश सचिव कानून विद हाईकोर्ट के अधिवक्ता अविनाश पाण्डेय के

मुताबिक भविष्यनिधि कार्यालय में 7ए की कार्यवाही चल रही है। वहां भी मालिकों व मिल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शम दाम दण्ड भेद करके मजदूरों के शोषण में लगे हैं। इस अमानवीय शोषण और उत्पीड़न का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके किसी भी बकाए का भुगतान किए बगैर ही उनसे जबर्न आवास भी खाली कराये जा रहे हैं। इसके लिए कर्मचारियों उमाशंकर पाल, राम तुलारे, राम सनेही, अशोक कुमार, सुमन, राम कुमार यादव, अनिल श्रीवास्तव विन्दा प्रसाद आदि की बिजली, पानी काट कर बेधर करने का भी कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश कर्मचारी बहुत दूर जा रहा क्षेत्रों के मूल निवासी हैं। चूँकि भविष्य में 7 ए ही कार्यवाही चल रही है। इसलिए वह वापस भी नहीं जा सकते।

हाई कोर्ट के जाने माने वकील और हिन्द मजदूर सभा के प्रदेश सचिव, अविनाश पाण्डेय ने यहां बताया कि इनके निकाले जाने का वाद

सरकार द्वारा अभिनिर्णय हेतु श्रम न्यायालय में भेज दिया गया है, जिससे नाराज होकर मालिकान उन्हें बेधर करने जैसी यह कार्यवाही कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इस अन्याय अत्याचार और शोषण की लगातार लिखित शिकायत किए जाने के बाद भी अपर श्रमायुक्त और सहायक श्रमायुक्त सीतापुर द्वारा भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जबकि उन्हें इस सम्बन्ध में स्थगन दिये जाने हेतु तमाम प्रार्थना पत्र, अभिलेख और कई कार्यस्थलों के आदेश भी निर्गत किये गये।

हिन्द मजदूर सभा के प्रदेश सचिव और पीड़ितों की आवाज बुलंद करने में भी अग्रणी उच्च न्यायालय के वकील अविनाश पांडेय ने यह भी बताया कि जिम्मेदार अधिकारियों के इस रवैये के खिलाफ कर्मचारियों की आवासीय सुविधा में पूर्ववत बहाल करने, उनके विरुद्ध की जा रहे किसी भी दण्डात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने के साथ-साथ उत्पीड़न, शोषण और

हो गई है, क्योंकि निकाले जाने के बाद कर्मचारियों के पास उनकी रोजी-रोटी का कोई भी जुगाड़ नहीं बचा है, जिसकी वजह से उनमें पैदा आक्रोश किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दिला सकता है, जिसकी जिम्मेदारी मिल प्रबंधन के साथ साथ शासन प्रशासन व श्रम विभाग की भी होगी।

फिलहाल फिलहाल गन्ना मिल मजदूरों के लगातार इस उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी देते हुए हिन्द मजदूर सभा के प्रदेश मंत्री हाई कोर्ट के अधिवक्ता अविनाश पाण्डेय ने सेवायोजकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने, भविष्य निधि सेवन ए ही कार्यवाही तथा उन्हें सेवाओं से जबर्न निकाले जाने का अभिनिर्णय वाद के अन्तिम निस्तारण व अनुपालन होने तक बिजली पानी बहाल कराते हुए सभी मजदूर कर्मचारियों की आवासीय सुविधा में पूर्ववत बहाल करने, उनके विरुद्ध की जा रहे किसी भी दण्डात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने के साथ-साथ उत्पीड़न, शोषण और

सऊदी अरब-पाकिस्तान रक्षा समझौता- इस्लामिक नाटो की नींव या नया भू-राजनीतिक संतुलन?

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया-वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को रियाद में ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है। इसके तहत किसी एक देश के खिलाफ किसी भी आक्रमण को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी के इस समझौते में कुछ और देशों के आने की चर्चा है। जियो न्यूज़ में पाक रक्षा मंत्री से पूछा गया कि क्या दूसरे अरब देश भी इस समझौता का हिस्सा बन सकते हैं। इसपर उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब समय से पहले नहीं दे सकता लेकिन मैं यह जरूर है कि दरवाजे खुले हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता केवल द्विपक्षीय सहयोग की औपचारिकता नहीं, बल्कि मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की भू-राजनीतिक दिशा बदलने वाला एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है। यह समझौता इस्लामिक वर्ल्ड में एक प्रकार के सामूहिक सुरक्षा ढांचे की कल्पना को जन्म देता है, जिसे कई विश्लेषक "इस्लामिक नाटो" की शुरुआत मान रहे हैं। समझौते के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी एक देश पर हमला पूरे समझौता ढांचे पर हमला माना जाएगा। इस प्रकार यह सुरक्षा गारंटी दोनों देशों के रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी में बदलती है। मुस्लिम देशों के बीच लंबे समय से यह बहस चल रही है कि क्या उन्हें भी यूरोप की तरह सामूहिक रक्षा तंत्र अपनाना चाहिए। ओआईसी (आर्गनाइजेशन ऑफ़ इस्लामिक कोऑपरेशन) में इस पर कई बार चर्चा हुई, लेकिन टोस कदम कभी नहीं उठाए गए। अब सऊदी-पाक रक्षा समझौते ने इस विचार को वास्तविकता के करीब ला दिया है। पाकिस्तान, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड की अकेली परमाणु शक्ति है, और सऊदी अरब, जो कि आर्थिक और धार्मिक नेतृत्व रखता है, का एक होना मुस्लिम दुनिया के लिए आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह संदेश भी दिया

गया है कि मुस्लिम राष्ट्रों को मिलकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करना एक मौलिक अधिकार है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावानी गोंदिया महाराष्ट्र मानता हूँ कि भारत, सऊदी अरब अमीरात व खाड़ी देशों के साथ प्रगाढ़ा संबंधों को बनाए रखने के लिए विदेश नीति को और मजबूत बनाने की जरूरत है। यह पूरी जानकारी मीडिया से उठाई गई है जो पिछले दो दिनों से सभी चैनलों और सोशल मीडिया पर चल रहा है।

साथियों बात अगर हम यह समझौता भारत के लिए चुनौती या अवसर? की करें तो भारत इस समझौते को मिश्रित भाव से देख रहा है। एक ओर, भारत और सऊदी अरब के संबंध बेहद मजबूत हैं, ऊर्जा आपूर्ति, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और जी20 सहयोग से लेकर निवेश तक। दूसरी ओर, पाकिस्तान भारत का कट्टर प्रतिद्वंद्वी है। यदि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ रक्षा गारंटी समझौते में शामिल होता है, तो भारत को आशंका होगी कि कहीं भविष्य में इस्लामिक रक्षा तंत्र भारत के खिलाफ इस्तेमाल न हो। खासकर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को हमेशा इस्लामिक देशों से राजनीतिक समर्थन मिलता रहा है। हालांकि सऊदी अरब ने हाल के वर्षों में संतुलित रुख अपनाया है, परंतु भारत के रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह डील भारत की विदेश नीति के लिए नई चुनौती लेकर आएगी। भारत और सऊदी अरब के संबंध पिछले दशक में ऐतिहासिक ऊँचाई पर पहुंचे हैं। भारतीय पीएम और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच कई साझेदारियों में ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सहयोग और रक्षा उद्योग शामिल हैं। भारत सऊदी अरब के लिए एक भरोसेमंद आर्थिक पार्टनर है। हालांकि पाकिस्तान-सऊदी रक्षा डील भारत-सऊदी रिश्तों को पूरी तरह कमजोर नहीं करेगी, परंतु उसमें "रणनीतिक अविश्वास" का तत्व जरूर जोड़ देगी। भारत यह देखना चाहेगा कि क्या यह



समझौता केवल आतंकवाद और क्षेत्रीय खतरों से लड़ने के लिए है, या भविष्य में यह किसी विशेष देश (अप्रत्यक्ष रूप से भारत) के खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है?

साथियों बात अगर हम इस रक्षा समझौते में अमेरिका की भूमिका पर सवाल पर विश्व की नजरों की करें तो, इस समझौते के समय और पृष्ठभूमि को देखते हुए यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या अमेरिका का इसमें कोई हाथ है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका प्रतिनिधियों की कई मुलाकातें सऊदी और पाक नेतृत्व से हुई हैं। अमेरिका की रणनीति अक्सर यह रही है कि वह मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बनाए रखे। ईरान का बढ़ता प्रभाव, चीन-सऊदी नजदीकियाँ, और पाकिस्तान की आर्थिक अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए वांछित शायद इस समझौते को अप्रत्यक्ष समर्थन दे रहा हो। अमेरिका का हित यह है कि सऊदी अरब उसके सुरक्षा तंत्र में बना रहे और पाकिस्तान उसके भू-राजनीतिक समीकरण से पूरी तरह चीन के पाले में न चला जाए। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका का परोक्ष

सहयोग या प्रोत्साहन इस समझौते के पीछे हो सकता है।

साथियों बात अगर हम वैश्विक स्तर पर इस्लामिक नाटो का विचार और संभावित प्रभाव की करें तो, यदि मुस्लिम राष्ट्र मिलकर एक नैस्य ढांचा खड़ा करते हैं तो यह सीधे-सीधे नाटो और यूरोपीय संघ जैसी व्यवस्था की झलक देगा। पहले ही "इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेरिज्मकोएल्लिशन" (आईएमपीसीटीसी) नाम से 34 मुस्लिम देशों का गठबंधन बना था, लेकिन वह सक्रिय नहीं रह सका। इस बार पाकिस्तान और सऊदी की जोड़ी इसे नई ऊर्जा दे सकती है। यदि यह ढांचा मजबूत हुआ तो यह पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना बदल देगा। ईरान, तुर्की, कतर और मिश्र की भूमिका इसमें निर्णायक होगी। यूरोप और अमेरिका के लिए यह चुनौती होगी कि उनके सामने एक नया सुरक्षा ब्याक खड़ा हो जाए, जो ऊर्जा संपन्नता और सामरिक स्थिति की वजह से बहुत प्रभावशाली होगा।

साथियों बात अगर हम यूरोप और पश्चिम के

लिए नई चुनौती यह चीन की प्रतिक्रिया की करें तो यूरोपीय संघ और नाटो अब तक मुस्लिम दुनिया को अलग-अलग देशों के रूप में देखते रहे हैं। यदि इस्लामिक रक्षा ढांचा अस्तित्व में आता है, तो यूरोप के सामने एक संगठित सैन्य-राजनीतिक शक्ति खड़ी होगी। यह चुनौती खासकर ऊर्जा सुरक्षा, हथियार बाजार और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए होगी। यूरोप और अमेरिका को अपने पारंपरिक "सुरक्षा प्रदाता" की भूमिका पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। साथ ही, यह भी संभव है कि इस्लामिक ब्याक रूस और चीन के साथ नए समीकरण बनाए, जिससे पश्चिम की भू-राजनीतिक पकड़ और कमजोर होगी। चीन और रूस की प्रतिक्रिया-चीन और रूस इस विकास को अपने हितों के अनुसार देखेंगे। चीन पाकिस्तान का पारंपरिक साझेदार है और सऊदी अरब के साथ भी प्रतिक्रिया-चीन और रूस इस विकास को अपने हितों के अनुसार देखेंगे। यदि इस्लामिक सुरक्षा तंत्र बनता है तो चीन उसे आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन दे सकता है ताकि अमेरिका का दबदबा कमजोर हो। रूस भी इसे पश्चिमी गठबंधनों के मुकाबले एक नया मंच मानकर ऊर्जा और हथियारों के सौदों के जरिए

इसमें प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। साथियों बात अगर हम भारत की कूटनीतिक रणनीति की करें तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वह सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्तों को बनाए रखे। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि पाकिस्तान-सऊदी रक्षा समझौते का भारत-सऊदी साझेदारी पर नकारात्मक असर न पड़े। इसके लिए भारत को ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों के हित और निवेश संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। साथ ही, भारत को अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदारों के साथ अपनी रणनीतिक समझ बढ़ानी होगी ताकि किसी संभावित "इस्लामिक नाटो" के दबाव को संतुलित किया जा सके।

साथियों बात अगर हम क्षेत्रीय समीकरण: ईरान और तुर्की की भूमिका की करें तो, ईरान इस समझौते को संदेह की निगाह से देखेगा क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ही ऐतिहासिक रूप से उसके प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। तुर्की अपने "इस्लामिक नेतृत्व" के दावे के चलते इसमें शामिल होने या न होने को लेकर दुविधा में रहेगा। यदि यह गठबंधन सुन्नी मुस्लिम देशों तक सीमित रहता है तो यह इस्लामिक वर्ल्ड में नई खाई भी पैदा कर सकता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे नया भू-राजनीतिक अध्याय, सऊदी अरब और पाकिस्तान का यह रक्षा समझौता न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड, दक्षिण एशिया और वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए सऊदी अरब के साथ ही उसके गहरे आर्थिक रिश्ते हैं। यह इस्लामिक नाटो जैसी संरचना की शुरुआत भी हो सकता है और साथ ही भारत जैसे देशों के लिए कूटनीतिक चुनौतियाँ भी पैदा करेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह कदम एक नए अध्याय की तरह है, जिसका असर आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा।

हरियाणा में तबादलों का संकट – शिक्षकों की उम्मीदों पर विराम

अप्रैल से इंटरज़ार, अब तक अधर में तबादले; मॉडल स्कूल का परिणाम टला, नई नीति भी अधूरी

हरियाणा में शिक्षकों के तबादले अप्रैल में होने थे, लेकिन आज तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। सरकार ने घोषणा की थी कि सबसे पहले मॉडल स्कूल का परिणाम आएगा और उसी के आधार पर तबादलों की दिशा तय होगी, परंतु महीनों बीत जाने के बावजूद यह परिणाम घोषित नहीं किया गया। अब नई तबादला नीति बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन वह नीति भी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। इस देरी से शिक्षक गहरे असमंजस में हैं। हजारों शिक्षक अपने परिवार से दूर कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद थी कि समय पर तबादलों से राहत मिलेगी। मगर सरकार के बार-बार बदलते वादों और अधूरी तैयारियों ने उनके धैर्य की परीक्षा ले ली है। अब ज़रूरत है कि सरकार तुरंत मॉडल स्कूल का परिणाम घोषित करे, नई नीति स्पष्ट करे और पारदर्शी तरीके से तबादला प्रक्रिया शुरू करे।

- डॉ. सत्यवान सौरभ

हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था इस समय गहरे असमंजस और ठहराव के दौर से गुजर रही है। अप्रैल से लेकर अब तक हजारों शिक्षक अपने तबादलों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन नतीजा यह है कि महीनों बाद भी कोई ठोस प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। सरकार और विभाग ने कई बार आश्वासन दिया कि जल्द ही तबादला ड्राइव चलेगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज तक न तो मॉडल स्कूल का परिणाम घोषित हुआ और न ही नई तबादला नीति लागू हो सकी। ऐसे में शिक्षकों के मन में असंतोष और धैर्य की सीमाएँ दोनों टूटती नज़र आ रही हैं।

हरियाणा में शिक्षकों के तबादले अप्रैल में होने थे, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पाए। सरकार ने पहले कहा था कि सबसे पहले मॉडल स्कूल का परिणाम घोषित किया जाएगा और फिर उसी के आधार पर तबादला ड्राइव चलाई जाएगी, मगर महीनों बीत जाने के बावजूद यह परिणाम जारी



नहीं हुआ। नई तबादला नीति बनाने की बात कहकर शिक्षकों को उलझाए रखा गया है, जबकि वह नीति भी अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। इस देरी से हजारों शिक्षक असमंजस और निराशा में हैं, क्योंकि कई शिक्षक कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और उन्हें समय पर स्थानांतरण से राहत की उम्मीद थी। लगातार वादों और अधूरी तैयारियों ने उनके धैर्य की परीक्षा ले ली है। अब ज़रूरी है कि सरकार तुरंत मॉडल स्कूल का परिणाम घोषित करे, नई नीति स्पष्ट करे और पूरी पारदर्शिता के साथ तबादला प्रक्रिया को आगे बढ़ाए।

तबादले किसी भी शिक्षक के लिए केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं होते। यह उनके निजी जीवन, पारिवारिक परिस्थितियों और पेशेवर संतुष्टि से गहराई से जुड़े होते हैं। वर्षों से एक ही स्थान पर काम कर रहे शिक्षकों को बदलाव की उम्मीद रहती है, वहीं दूरदराज़ क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को अपने परिवार और बच्चों से जुड़ने की चाह होती है। जब यह उम्मीदें लगातार अधूरी रह जाती हैं, तो उसका असर उनके मनोबल और कार्यक्षमता दोनों पर पड़ता है।

अप्रैल में सरकार ने दावा किया था कि सबसे पहले मॉडल स्कूल का परिणाम घोषित किया जाएगा और उसके आधार पर तबादलों की प्रक्रिया को दिशा दी जाएगी। लेकिन यह परिणाम महीनों से लटक चुका है। इसके साथ ही सरकार ने नई तबादला नीति बनाने की घोषणा की, ताकि प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो

सके। यह घोषणा सुनने में आकर्षक ज़रूर थी, लेकिन जब नीति महीनों तक अधर में ही पड़ी रहे और शिक्षकों को उसका कोई स्पष्ट स्वरूप न दिखे, तो यह केवल समय खींचने का बहाना प्रतीत होता है।

इस पूरी देरी का सीधा असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। जहाँ कुछ स्कूलों में ज़रूरत से ज्यादा शिक्षक मौजूद हैं, वहीं कई ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में वर्षों से पद खाली पड़े हैं। नतीजा यह है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और असमानता बढ़ रही है। मॉडल स्कूल परियोजना, जिसे शिक्षा सुधार का प्रतीक बताया गया था, उसका परिणाम ही न आना सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है।

शिक्षक लगातार धैर्य बनाए हुए हैं, लेकिन अब उनकी आवाज़ें तेज़ होने लगी हैं। संघ और संगठन यह सवाल पूछ रहे हैं कि जब पुरानी नीति के तहत ही प्रक्रिया पूरी हो सकती थी, तो उसे बीच में क्यों रोका गया। नई नीति का हवाला देकर महीनों तक शिक्षकों को उलझाए रचना क्या केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी नहीं दर्शाता? शिक्षकों का मानना है कि सरकार को यदि सचमुच पारदर्शिता चाहिए तो नीति को सार्वजनिक करना चाहिए। यदि वह तैयार नहीं है तो पुरानी नीति के तहत प्रक्रिया शुरू करना चाहिए, ताकि कम से कम शिक्षकों को राहत मिल सके।

हरियाणा जैसे राज्य में, जहाँ शिक्षा सुधार और मॉडल स्कूलों की बातें बड़े स्तर पर की जाती

रही हैं, वहाँ आज स्थिति यह है कि शिक्षकों को अपने ही भविष्य का पता नहीं। यह केवल शिक्षकों का संकट नहीं है, बल्कि छात्रों और पूरी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न है। शिक्षक असंतुष्ट और परेशान रहेंगे तो वे बच्चों को पूरी निष्ठा से कैसे पढ़ा पाएंगे?

अब जबकि सितंबर भी समाप्त की ओर है, सरकार को और देरी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मॉडल स्कूल का परिणाम घोषित करना ज़रूरी है, ताकि शिक्षकों को स्पष्टता मिल सके। इसके बाद नई नीति को सार्वजनिक करना चाहिए और यदि वह अधूरी है तो पुरानी नीति के तहत ही तबादला प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल और समयबद्ध तरीके से हो, ताकि किसी प्रकार का पक्षपात या अनुप्रांसा की गुंजाइश न रहे।

अंततः यह समझना होगा कि शिक्षक केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि परेशान की रीढ़ हैं। उन्हें महीनों तक अनिश्चितता और प्रतीक्षा में रखना उनके साथ अन्याय है और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। यदि सरकार सचमुच शिक्षा सुधार चाहती है, तो उसे तुरंत ठोस और पारदर्शी कदम उठाने होंगे। हरियाणा के शिक्षकों का धैर्य अब अंत की ओर है, और यह समय है कि सरकार वादों और घोषणाओं से आगे बढ़कर वास्तविक कार्रवाई करे। देगा एकमात्र रास्ता है जो शिक्षकों को न्याय देगा और हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को संतुलन और मजबूती प्रदान करेगा।

दिव्यांगजन की आवाज़: मुख्यधारा से जुड़ने की पुकार

भारत में करोड़ों दिव्यांगजन आज भी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सार्वजनिक जीवन में एहिए पर हैं। संवैधानिक अधिकारों और २०16 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के बावजूद सामाजिक पूर्वाभा, हांवागत बाधाएँ और मौडिया में विकृत छवि उनकी गरिमा को चोट पहुँचाती हैं। सुप्रिम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि उनकी समानता और सम्मान से सम्बन्धिता नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि समाज सहजभूति से आगे बढ़कर दिव्यांगजन को अधिकार और अवसर दे। तकनीक, जागरूकता, कानून का सख्त क्रियाव्यवहन और सक्रिय भागीदारी ही समावेशी भारत की कुंजी हैं।

- डॉ. प्रियंका सौरभ

माँसीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता और समावेशिता मानी जाती है। संवैधानिक ने हर नागरिक को समान अधिकार, गरिमा और अवसर की गारंटी दी है। परन्तु जब हम समाज के उस वर्ग की ओर देखते हैं, जिन्हें दिव्यांगजन कहा जाता है, तो यह गारंटी अवसर छोड़ती दिखती है। देश की जगजगता और साक्षात् सर्वद्वेषन इस बात की पुष्टि करते हैं कि करोड़ों दिव्यांगजन आज भी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवागत, मौडिया और सार्वजनिक जीवन में एहिए पर हैं। संवैधानिक प्रावधान और कानून मौजूद हैं, परन्तु ज़मीनी स्तर पर उनकी स्थिति इस सत्य को बयान करती है कि वे अब भी अदृश्य नागरिकों की तरह जीवन जीते हैं।

समस्या केवल मौडिक अवरोधों की नहीं है, बल्कि मानसिकता और दृष्टिकोण की भी है। समाज का बड़ा हिस्सा अब भी दिव्यांगता को दया, बेर या भास्य की दृष्टि से देखता है। यह सोच जगजगता और साक्षात् सर्वद्वेषन को नकार देती है। उन्हें बराबरी का अवसर देने के बजाय या तो दया का पात्र बना दिया जाता है या हसी का दिव्य। भारतीय सिनेमा और टीवीविजन ने भी लंबे समय तक इसी रूढ़ियों को दोहराया है। हालाँकि अब धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है, परन्तु वह बदलाव बहुत धीमा और सीमित है। भारतीय व्यापारिक ने कई बार दिव्यांगजन की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। सुप्रिम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता या सत्य के नाम पर किसी भी समुदाय की गरिमा से सम्बन्धिता नहीं किया जा सकता। शल ही नें दिए गए फैसलों में मौडिया और मनोरंजन उद्योग को चेतावनी गयी कि वे दिव्यांगजन को नज़ाकत या दया का पात्र न बनाएँ, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करें। इसके बावजूद, समाज में गहरे ज़ेने पूर्वाभाब अब भी मौजूद हैं।

व्यार्षिक कुनूती केवल कानूनी संरक्षण से पूरी नहीं होती। समस्या यह है कि कानून और नीतियों लागू करने वाली संस्थाओं में व्यक्त संवैधानिकता और दृढ़ता का अभाव है। उदाहरण के लिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में अंधे हुए आरक्षण और सुविधाओं की गारंटी दी। परन्तु स्कूलों और कॉलेजों की इमारतें अब भी सीढ़ियों से नहीं हैं, सरकारी दफ्तरों में क्लींवेयर के लिए जगह नहीं है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब भी दृष्टिबाधित या अग्रगण्यता लोगों के लिए आवश्यक विकल्प उपलब्ध नहीं कर पाते।

दिव्यांगजन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें "सहज नागरिक" के बजाय "निर्धर नागरिक" मान लिया गया है। यह सोच उन्हें समाज की मुख्यधारा से दूर कर देती है। जबकि सच्चाई यह है कि अवसर और सुविधा मिलने पर दिव्यांगजन किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता साधित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिव्यांगजन के लिए आवश्यक विकल्प उपलब्ध नहीं कर पाते।

दिव्यांगजन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें "सहज नागरिक" के बजाय "निर्धर नागरिक" मान लिया गया है। यह सोच उन्हें समाज की मुख्यधारा से दूर कर देती है। जबकि सच्चाई यह है कि अवसर और सुविधा मिलने पर दिव्यांगजन किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता साधित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिव्यांगजन के लिए आवश्यक विकल्प उपलब्ध नहीं कर पाते।

दिव्यांगजन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें "सहज नागरिक" के बजाय "निर्धर नागरिक" मान लिया गया है। यह सोच उन्हें समाज की मुख्यधारा से दूर कर देती है। जबकि सच्चाई यह है कि अवसर और सुविधा मिलने पर दिव्यांगजन किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता साधित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिव्यांगजन के लिए आवश्यक विकल्प उपलब्ध नहीं कर पाते।

गया। मकैल ने यह निर्णय मानवीय आधार पर लिया था लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यावहारिकता से भी प्रेरित था। अमेरिका समाचार चैनल सीसीएनएन ने इसको लेकर एक डिटेल रिपोर्ट छापी है। सीएनएन से बातचीत में हिल्डेशाइम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हानेस शमैन ने कहा- मकैल का उद्देश्य अन्य यूरोपीय देश इस संकट से निपटने के लिए तैयार नहीं थे हालांकि, इस निर्णय ने जर्मनी के सामने अप्रत्याशित चुनौतियाँ पैदा कर दी हैं। जर्मनी में एक दशक में करीब दो करोड़ लोगों ने शरण के लिए आवेदन किया बताया जा रहा है।

2015 में जर्मनी के लोगों ने शरणार्थियों का स्वागत गर्मजोशी से किया. म्यूनिख में स्थानीय लोग शरणार्थियों को भोजन और पानी बाँटने के लिए सड़कों पर उतरे. अनस मोदमानी जैसे शरणार्थी जो 17 साल की उम्र में सीरिया से भागकर जर्मनी पहुँचे, इसे अपने जीवन का सबसे अच्छा पल बताया लेकिन यह स्वागत संस्कृति ज्यादा समय तक नहीं टिकी। 2016 की नववर्ष की पूर्व संध्या पर कोलोन में महिलाओं पर सामूहिक यौन हमलों की घटना हुई। इसमें शरणार्थियों को दोषी ठहराया गया। इस घटना ने मकैल की नीतियों पर सवाल उठाए और सामाजिक माहौल को बदल दिया। इस घटना ने दक्षिणपंथी दल अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी को एक नया मंच प्रदान किया। उस वक़्त तक इराक़ दल को जर्मनी में बहुत परंपद नहीं किया जाता था। 2013 में स्थापित यह पार्टी एहिए पर थी। यह पार्टी की नीतियाँ काफी हद तक हिटलर की नीति से प्रभावित हैं। यह अब जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन चुकी है। एएफडी ने शरणार्थी-विरोधी और आप्रवासन-विरोधी भावनाओं को हवा दी, जिसका असर हाल के चुनावों में साफ दिखाई देता है। इस बात की पुष्टि इस रिपोर्ट से होती है कि 2015 में केवल 38 फीसदी जर्मन शरणार्थियों की संख्या कम करने के पक्ष में थे लेकिन 2025 तक यह आंकड़ा 68 फीसदी तक पहुँच गया है। यानी अब जर्मन जनता शरणार्थियों को संसद नहीं कर रही है।

वमकैल की पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक

क्षमता का तोस बनवाया है। समस्या क्षमता की नहीं, बल्कि अवसर और दृष्टिकोण की है।

यदि समाज समुच्च समावेशी बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसकी सोच बदलनी होगी। दिव्यांगजन को दया या सहजभूति की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बराबरी के अधिकार और अवसर चाहिए। स्कूलों में बच्चय से ही बच्चों को यह सिखाना लेना कि विक्रमता ही समाज की ताकत है। मौडिया और सिनेमा को डिस्मेटरी लेनी होगी कि वे दिव्यांगता को केवल दुर्भाग्य के रूप में दिखाने, बल्कि उसे साहस, आत्मविश्वास और मानवीय गरिमा से जोड़कर पेश करें।

सार्वजनिक दाये को दिव्यांगजन की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। नेट्रो स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस अड्डे, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, पार्क और शैक्षणिक संस्थान सब तब तक समावेशी नहीं करे जा सकते, जब तक वे हर व्यक्ति के लिए सुलभ न हों। तकनीकी प्रगति इस दिशा में बहुत मददगार हो सकती है। डिजिटल ऐप में वॉइस अड्रिस्ट, स्क्रीन रीडर और सॉफ्टवेयर भाषा की सुविधाएँ जोड़कर हम लाखों दिव्यांगजन को अंतर्भावित शिक्षा और रोजगार से जोड़ सकते हैं। समानता की इस तड़प में सरकार और समाज दोनों की साझी भूमिका है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिव्यांगजन के लिए बनाए गए कानून केवल कानून बूझाएँ दस्तावेज़ बनकर न रह जाँएँ। उनके प्रभावी क्रियाव्यवहन के लिए स्वतंत्र निगरानी तंत्र बने। स्थानीय निकायों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक निर्णय प्रक्रिया में दिव्यांगजन की भागीदारी हो। उनकी ज़रूरतों और सुझावों को सुने बिना कोई नीति या योजना पूरी नहीं हो सकती।

वहीं समाज की भूमिका और भी बड़ी है। हर व्यक्ति को अपने घर, मोस्ले और कार्यस्थल पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिव्यांगजन सम्मान और बराबरी के साथ भी सके। सार्वजनिक कार्यक्रमों, चुनावी रैलियों और सांस्कृतिक आयोजनों में उनकी भागीदारी बढ़े। यह तभी संभव है जब हम उन्हें दया नहीं, अधिकार का दर्जा दें।

भारत का संवैधानिक हने बराबरी, गरिमा और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा इन अधिकारों से वंचित रहता है, तो लोकतंत्र अक्षर तः जाता है। दिव्यांगजन को एहिए से मुख्यधारा में लाना केवल मानवता का कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की बुनियादी शर्त भी है। जब तक दिव्यांगजन की आवाज़ नीतियों और समाज दोनों में बराबर न सुनी जास्की, तब तक समावेशी भारत का सपना अक्षर रहेगा।

इसलिए आज समय की सबसे बड़ी पुकार यह है कि दिव्यांगजन को अदृश्य नागरिक नहीं, बल्कि परदेवित और प्रगति के सक्रिय साझेदार बना जाएँ। उनकी क्षमताओं और सपनों को पहचान कर ही हम इस समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ कोई पीछे न छोटे।

किसान ही गरीब क्यों - वह ऐसा ही रहेगा

फटेहाल : कब हो पायेगा खुशहाल!

चंद्र मोहन

दुनिया में हर इंसान भूख मिटाने और पोषण के लिए खाना खाता है. भोजन की आवश्यकता हर दिन तीन बार तो होती ही है जिसके लिए उसे किसान पर निर्भर रहना होता है.

प्रदेश और मौसम के अनुसार ही किसान फल और सब्जियों का उत्पादन करता है.

सभी जगह गेहूँ, चावल, फल और सब्जियों के लिए ज़मीन होना ज़रूरी है.

भारत गाँवों का देश है. किसान आवश्यकता अनुसार नवीन तैयार करता है. फिर धूप, पानी और मौसम को झेलते हुए अपनी फसल को उगाने में मेहनत करता है.

देश का किसान खूब मेहनत करता है फिर भी आखिर गरीब क्यों है ?

कृषि सुधार कानून वापस हो गए हैं तो क्या हुआ ? अब समय है कि कृषि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए.

किसान अक्सर गरीब होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता, उनकी भूमि छोटी होती है, उन्हें कर्ज का सामना करना पड़ता है और वे उन्नत तकनीकों तक पहुँच नहीं पाते हैं.

यहाँ कुछ और कारण दिए गए हैं:

भूमि का छोटा आकार - भारत में अधिकांश किसानों के पास छोटी और खंडित भूमि होती है, जिससे वे उन्नत तकनीकों को अपनाने और अपनी आय बढ़ाने में असमर्थ होते हैं.

फसलों का उचित मूल्य न मिलना - किसानों को अक्सर अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है, जिससे वे कर्ज में डूब जाते हैं और गरीबी में फंस जाते हैं.

कर्ज का बोझ - कई किसान ऋण लेते हैं, लेकिन वे अपनी फसल से पर्याप्त आय नहीं कमा पाते हैं, जिससे वे कर्ज में फंस जाते हैं.

तकनीकों तक पहुँच की कमी - कई किसानों को उन्नत तकनीकों और संसाधनों तक पहुँच नहीं होती है जिससे उनकी उपज कम होती है और वे गरीबी में रहते हैं.

शिक्षा और कोशल की कमी -



कई किसान अशिक्षित होते हैं और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी नहीं होती है जिससे वे अपनी आय बढ़ाने में असमर्थ होते हैं.

कृषि में कम आय - भारत में कृषि आय कम होती है जिससे किसान गरीबी में रहते हैं.

खाद्य सुरक्षा - भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जाती हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ सभी किसानों तक नहीं पहुँच पाता है.

मौसम परिवर्तन - जलवायु परिवर्तन और मौसम की अनिश्चितता के कारण किसानों को भारी नुकसान होता है जिससे उनकी आय कम हो जाती है.

कृषि भूमि का क्षरण - लगातार खेती के कारण कृषि भूमि का क्षरण हो रहा है जिससे किसानों की आय कम हो रही है.

सरकारी नीतियों की कमी - सरकार की नीतियों में किसानों के हितों को अनदेखी की जाती है जिससे वे गरीबी में रहते हैं.

अनुमान के मुताबिक देश में फल-सब्जियों का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा खराब हो जाता है। जल्दी खराब होने वाली उपज के भंडारण की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने से ऐसा होता है।

गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की विधिवत

व्यवस्था नहीं होने के कारण अधिक उत्पादित उपज किसान फेंकने के लिए बाध्य होते हैं. इस संबंध में सही नीति बने तो निवेश की राह भी आसान हो. विदेशी कंपनियों के निवेश के साथ ही तकनीक भी आती है. गाँवों में पैदा होने वाली उपज का वहीं भंडारण और प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) होने लगे तो बड़े पैमाने पर वहाँ रोजगार के अवसर भी बनेंगे. शहरों की ओर युवाओं का पलायन भी कम होगा.

कृषि कानून इन समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सकते थे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. अब हमें आगे की राह देखनी होगी. हमें समझना होगा कि अब पूरा विश्व एक बाजार होता जा रहा है. किसी भी देश में कहीं से भी अनाज, फल, सब्जी खरीदना-बेचना संभव है. भारत के किसानों को दुनिया के किसानों से मुकाबला करना है तो जो तकनीक, बीज दूसरे देश के किसान इस्तेमाल करते हैं, उनको उपलब्धता भारत के किसानों तक भी होनी चाहिए.

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली-पानी की सुदृढ़ व्यवस्था और अच्छी सड़कें भी बहुत ज़रूरी हैं. इससे बाजार तक किसानों की पहुँच सुगम होती है. इससे उन्हें उत्पादों की सही कीमत मिल पाती है. इन सब मसलों पर कदम उठाए जाएँ तो कुछ ही साल में कृषि का नक्शा बदल सकता है. किसानों को आंदोलन की राह छोड़नी होगी. तभी अन्वयादा कहलाने वाले किसान फटेहाल से खुशहाल हो सकते हैं.

शरणार्थियों के स्वागत का निर्णय आज जर्मनी

की सबसे बड़ी समस्या बन कर उभरा है

रामस्वरूप रावतसर

जर्मनी पहले और द्वितीय विश्वयुद्ध के समय यह देश दुनिया के बेताज बादशाह था।

उत्तरे के बाद के दिनों में भी यह यूरोप की एक सबसे बड़ी ताकत थी लेकिन बीते एक दशक में यहाँ बहुत कुछ बदला है। कई बार ऐसा होता है कि सदियों से चली आ रही चीजें महज कुछ वर्षों में पूरी तरह बदल जाती हैं। आमतौर पर हम बेहद तेज़ गति से हुए ऐसे बदलावों की उम्मीद नहीं करते हैं लेकिन चाहे-अनचाहे ऐसा हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है दुनिया के एक बड़े मुल्क के साथ। यह ऐसा मुल्क है जिसकी कभी पूरी दुनिया में तूती बोलती थी लेकिन बीते एक दशक में इस देश में भयंकर रूप से बदलाव हुआ है। यहां अचानक से इस्लाम मानने वाले मुस्लिम आबादी में भयंकर रूप से इजाफा हुआ है।

दरअसल, 10 साल पहले 2015 में जर्मनी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था जब तत्कालीन चांसलर एंजेला मर्केल ने सीरिया, अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्धग्रस्त और आर्थिक रूप से अस्थिर देशों से आने वाले लाखों शरणार्थियों के लिए अपने देश के दरवाजे खोल दिए। मर्केल का यह कदम स्वागत संस्कृति के रूप में जाना गया, उस समय वैश्विक सुर्खियों में छाया रहा लेकिन शरणार्थियों का प्रमुख रजनीतिक और सांस्कृतिक ताने-बाने पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इससे जर्मनी की राजनीति और सामाजिक धारणाओं को नया आकार मिला है।

वर्ष 2015 में जब सीरिया में गृहयुद्ध अपने चरम पर था और अफगानिस्तान व इराक जैसे देश हिंसा और अस्थिरता से जूझ रहे थे, तब लाखों लोग सुरक्षित आश्रय की तलाश में यूरोप की ओर बढ़े। यूरोप में जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जो आर्थिक रूप से स्थिर और समृद्ध है। यह देश इन शरणार्थियों का प्रमुख गंतव्य बन गया. 2015 और 2016 में जर्मनी में 11.64 लाख लोगों ने पहली बार शरण के लिए आवेदन किया। इसमें से अधिकांश सीरिया, अफगानिस्तान और इराक से थे। 2015 से 2024 तक यानी नौ वर्षों में कुल 26 लाख आवेदन आए। इस तरह जर्मनी यूरोपीय संघ में ऐसे आवेदन हासिल करने वाला शीर्ष देश बन

गया। मर्केल ने यह निर्णय मानवीय आधार पर लिया था लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यावहारिकता से भी प्रेरित था। अमेरिका समाचार चैनल सीसीएनएन ने इसको लेकर एक डिटेल रिपोर्ट छापी है। सीएनएन से बातचीत में हिल्डेशाइम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हानेस शमैन ने कहा- मर्केल का उद्देश्य अन्य यूरोपीय देश इस संकट से निपटने के लिए तैयार नहीं थे हालांकि, इस निर्णय ने जर्मनी के सामने अप्रत्याशित चुनौतियाँ पैदा कर दी हैं। जर्मनी में एक दशक में करीब दो करोड़ लोगों ने शरण के लिए आवेदन किया बताया जा रहा है। 2015 में जर्मनी के लोगों ने शरणार्थियों का स्वागत गर्मजोशी से किया. म्यूनिख में स्थानीय लोग शरणार्थियों को भोजन और पानी बाँटने के लिए सड़कों पर उतरे. अनस मोदमानी जैसे शरणार्थी जो 17 साल की उम्र में सीरिया से भागकर जर्मनी पहुँचे, इसे अपने जीवन का सबसे अच्छा पल बताया लेकिन यह स्वागत संस्कृति ज्यादा समय तक नहीं टिकी। 2016 की नववर्ष की पूर्व संध्या पर कोलोन में महिलाओं पर सामूहिक यौन हमलों की घटना हुई। इसमें शरणार्थियों को दोषी ठहराया गया। इस घटना ने मर्केल की नीतियों पर सवाल उठाए और सामाजिक माहौल को बदल दिया। इस घटना ने दक्षिणपंथी दल अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी को एक नया मंच प्रदान किया। उस वक़्त तक इराक़ दल को जर्मनी में बहुत परंपद नहीं किया जाता था। 2013 में स्थापित यह पार्टी एहिए पर थी। यह पार्टी की नीतियाँ काफी हद तक हिटलर की नीति से प्रभावित हैं। यह अब जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन चुकी है। एएफडी ने शरणार्थी-विरोधी और आप्रवासन-विरोधी भावनाओं को हवा दी, जिसका असर हाल के चुनावों में साफ दिखाई देता है। इस बात की पुष्टि इस रिपोर्ट से होती है कि 2015 में केवल 38 फीसदी जर्मन शरणार्थियों की संख्या कम करने के पक्ष में थे लेकिन 2025 तक यह आंकड़ा 68 फीसदी तक पहुँच गया है। यानी अब जर्मन जनता शरणार्थियों को संसद नहीं कर रही है।

वमकैल की पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक

प्रधानमंत्री मोदी जी का सफर, भारत की राजनीति का स्वर्णिम अध्याय

डॉ. मुश्ताक अहमद शाह,

प्रधानमंत्री मोदी जी का राजनीतिक सफर भारतीय राजनीति का एक ऐसा उत्कृष्ट अध्याय है जिसे आने वाली पीढ़ियाँ लंबे समय तक स्मरण करेंगी। यह केवल सत्ता का सफर नहीं बल्कि एक ऐसे नेता की यात्रा है जिसने साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर भारतीय राजनीति और जनमानस पर गहरी छाप छोड़ी। आज जब दब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर संभवतः राजनीतिक संस्था की ओर बढ़ रहे हैं, या अविध्य में उनकी अपनी पार्टी के लिए क्या भूमिक रहेगी ये विषय अविध्य के गर्भ में छुपा हुआ विशिष्ट प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा देश एक ऐसे व्यक्तित्व को देख रहा है जिसने २1वीं सदी के भारत की दिशा और रूपा दोनों बदल डाली। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म गुजरात के वडनगर में एक साधारण परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही उन्होंने कठिन

परिस्थितियों में जीवन बीया और संघर्ष के बीच नेतृत्व तथा संगठन कौशल की शलक दिखानी शुरू कर दी। आगे चलकर वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और फिर भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाई। राजनीति में उनकी उमरती हुई छवि अनुशासन, परिश्रम और ज़मीनी स्तर के अनुभव पर आधारित थी। २001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके नेतृत्व ने एक नए प्रकार की विकासशील राजनीति को नया दिशा दी। उनके कार्यकाल में गुजरात ने आर्थिक गतिविधियों, आध्यात्मिक दर्शन और निवेश के क्षेत्र में मुत्लेखनीय प्रगति की, जिसने उन्हें "विकास पुरुष" की पदवी दिलाई। २014 का आम चुनाव भारतीय राजनीति का निर्णायक मोड़ साबित हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। यह दब क्षण था जब जनता ने कांग्रेस शासित लंबे दौर के बाद भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया।

प्रधानमंत्री मोदी जी ने "सबका साथ, सबका विकास" का आह्वान कर जनता की आकांक्षाओं को नई ऊर्जा दी। उन्होंने शासन को तकनीक-आधारित और मरिद्वयभागी कर दिया। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों ने नई पीढ़ी को स्वल्प और अवसर दोनों दिए। विदेश नीति के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी जी का दृष्टिकोण बेद्व सक्रिय और निर्णायक रहा। उन्होंने भारत की छवि को वैश्विक मंच पर अधिक प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। पड़ोसी देशों से संबंधों में सुधार लाने का प्रयास किया, पश्चिमी दुनिया और एशियाई देशों के साथ नए अठबंधन बनावे तथा संयुक्त राष्ट्र और जी-२0 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति मजबूत की। उनकी विदेश यात्राएँ और वैश्विक वाणी ने भारत को नई परभाव दिलाई प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में कई

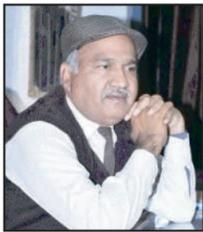
ऐतिहासिक निर्णय किए गए। नोटबंदी का कदम मरिद्वयार और कोले धन पर चोट के रूप में लिया गया, हालाँकि इस पर बहस और आलोचना भी बहुत हुई। "एक देश, एक कर" के रूप में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का लागू होना भारत की कर-व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन था। सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक रही जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटाना, जो लंबे समय से देश के राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रहा था। इसके अलावा, राम मंदिर निर्माण को गति देना, नागरिकता संशोधन कानून और कृषि सुधार कानून जैसे कई निर्णय उनके कार्यकाल के प्रमुख बिंदु रहे। इन कदमों ने उनके समर्थकों की नज़रों में उन्हें राष्ट्रप्रेमी नेता बनाया, वहीं आलोचकों ने उन्हें असंयत और टकराव बढ़ाने वाला बताया।

प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत करिश्मे और जनता से

उनके संबंध ने उन्हें भारतीय राजनीति का अज्ञा नेता बनाया। उनकी वक्तृत्व कला ने जन-समुदाय को सम्मोहित किया। "नन की बात" जैसे रेडियो कार्यक्रमों के जरिए उन्होंने करोड़ों लोगों से सीधा संवाद किया और सोशल मीडिया का अमूर्तपूर्ण उपयोग कर जनता में नई ऊँचाईयें हुईं। उनकी चुनावी रणनीति और संगठन क्षमता ने भाजपा को भारत की सबसे मजबूत राजनीतिक शक्ति बना दिया। अब उनके प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के साथ ही सवाल उठ खड़ा हुआ है कि भारतीय राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह निर्णय केवल सत्ता से विदाई नहीं, बल्कि एक युग का अंत है। उनके समर्थक उन्हें आधुनिक भारत को नई परभाव देने वाला नेता मानते हैं, जबकि आलोचक उनकी नीतियों के दीर्घकालिक प्रभावों पर विमर्श कर रहे हैं। हालाँकि इतना स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीति यात्रा

एक मिसाल है कि कैसे संकल्प और दूरदृष्टि के बल पर कोई नेता देश की आम जनता की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय राजनीति और शासन की धारा में बतल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की विरासत इतलसे में उनके निर्णयों, सुधारों और उनके द्वारा निर्मित राजनीतिक-सामाजिक धाराओं के आधार पर आँकी जास्की। उन्होंने भारत में एक ऐसा नेतृत्व मॉडल प्रस्तुत किया जो करिश्मा, संगठन शक्ति, निर्णायक निर्णय और जनता से संवाद की क्षमता पर आधारित था। यह यात्रा केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की नहीं, बल्कि उस भारत की है जो निरंतर बदलाव और प्रगति की ओर अग्रसर है। निरिधत रूप से, प्रधानमंत्री मोदी जी का यह इस्तीफा केवल पद त्याग नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के एक स्वर्णिम युग का समापन है। एक ऐसा युग जिसे आने वाली पीढ़ियाँ विस्तार से समझेगी और याद करेंगी।

वैज्ञानिक की खोज का अनुमान है कि सबसे लंबे समय तक मनुष्य रह सकते हैं, और रहस्य आहार, व्यायाम या ध्यान नहीं है



विजय गर्ग



मनुष्य कब तक रह सकता है? हर पीढ़ी ने एक ही सवाल पूछा है: मानव सबसे लंबे समय तक क्या रह सकता है? कुछ लोगों का मानना था कि इसका जवाब आनुवंशिकी में छिपा है, अन्य सख्त आहार या ध्यान प्रथाओं में हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने आखिरकार शरीर के आंतरिक कामकाज पर गहरी नजर डाली है। पहलने योग्य उपकरणों से हजारों रक्त परीक्षण और गतिविधि पैटर्न का विश्लेषण करके, शोधकर्ताओं ने एक आश्चर्यजनक सुराग की खोज की होगी। खोज केवल बीमारियों या स्वस्थ आदतों के बारे में बात नहीं करती है, यह कुछ और मौलिक की ओर इशारा करती है।

जीवन प्रत्याशा बनाम जीवनकाल
जीवन प्रत्याशा, औसत वर्ष लोग रहते हैं, बेहतर दवा, पोषण और स्वच्छता के लिए दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जीवन काल, अधिकतम वर्ष एक मानव शरीर जीवित रह सकता है, लगता है कि एक प्राकृतिक छत है। अग्रिमों के बावजूद, कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, और लगभग कोई भी एक निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ता है। यह नया शोध बताता है कि जीव विज्ञान स्वयं इस ऊपरी सीमा को निर्धारित करता है।

आनुवंशिक सीमा, सेलुलर उम्र बढ़ने और आणविक क्षति जैसे कारक यह परिभाषित करते हैं कि मानव शरीर अंततः कब तक कार्य कर सकता है।

DOSI के साथ कोड को क्रैक करना
उम्र बढ़ने को समझने के लिए, वैज्ञानिकों ने डायनेमिक ऑर्गेनिज्म स्टेट इंटीकेटर (DOSI) नामक

एक उपकरण बनाया। यह मापता है कि रक्त परीक्षण डेटा और आंदोलन पैटर्न का उपयोग करके शरीर तनाव का जवाब कैसे देता है। जन्मदिन की गिनती के विपरीत, DOSI बताता है कि कितनी जल्दी एक शरीर रोजमर्रा के पहलने और आंसू से उबर सकता है। समय के साथ, DOSI एक स्पष्ट प्रवृत्ति दिखाता है: रिकवरी लोगों की उम्र के रूप में धीमी हो जाती है, जो एक अंतिम सीमा की ओर इशारा करती है। यह खोज स्वास्थ्य में गिरावट की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकती है, एंटी-एजिंग उपचारों का मार्गदर्शन कर सकती है, और यह बता सकती है कि विश्व स्तर पर दीर्घायु और मानव जैविक लचीलापन को कैसे समझा जाता है।

रहस्य लचीलापन में निहित है
लचीलापन जीवन की छिपी मुद्रा है। यह शरीर की तनाव को ठीक करने, ठीक करने और अनुकूलित करने की शक्ति है। युवाओं में, यह वसूली त्वरित और कुशल है, और आप तेजी से वापस उछाल देते हैं। उम्र के साथ,

लचीलापन कमजोर हो जाता है, एक लुप्त होती वस्तु की तरह अपनी उछाल खो देता है। अध्ययन के अनुसार, टिपिंग बिंदु तब आता है जब लचीलापन पूरी तरह से खो जाता है। उस स्तर पर, एक विशिष्ट बीमारी के बिना भी जीवित रहना असंभव हो जाता है।

स्वस्थ आदतों, सामाजिक कनेक्शन और मानसिक कल्याण के माध्यम से लचीलापन बनाए रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। यह केवल लंबे समय तक जीने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन, स्वतंत्रता और जीवन शक्ति की गुणवत्ता को संरक्षित करने के बारे में है जो उन अतिरिक्त वर्षों को वास्तव में सार्थक बनाते हैं अधिकांश अधिकतम तक क्यों नहीं पहुंचते

हालांकि शोध का अनुमान है कि मनुष्य 120-150 साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन बहुत कम लोग करीब आते हैं। पुरानी बीमारियाँ, तनाव, धूम्रपान, खराब आहार और पर्यावरणीय चुनौतियाँ बहुत पहले लचीलापन से दूर हो जाती हैं। अध्ययन से पता चला है

कि धूम्रपान जैसे कुछ हानिकारक प्रभावों को कभी-कभी समय पर रोकने पर उलटा किया जा सकता है, जिससे खुद को ठीक करने का मौका मिलता है।

आज के युग के लिए सबक
आधुनिक जीवन शैली छिपे हुए जोखिमों से भरी होती है: प्रदूषण, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और निरंतर तनाव। ये न केवल जीवन को छोटा करते हैं बल्कि स्वास्थ्य को भी कम करते हैं, वर्ष अर्द्ध स्वास्थ्य में रहते थे। अध्ययन सिर्फ बीमारियों से बचने के लिए नहीं, बल्कि लचीलापन की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। छोटे विकल्प, आराम, वसूली, आंदोलन, और हानिकारक आदतों से बचने, बुढ़ापे की ओर यात्रा चिकनी कर सकते हैं, भले ही वे जैविक अधिकतम का विस्तार नहीं कर सकते।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद, गली कोर चंद एमएचआर मलोट पंजाब



संपादकीय

चिंतन-मनन



व्यंग्य : रिपेयरिंग करवा लो , मरम्मत करवा लो टूटी बिल्डिंग , टूटे हुए घर की

बरसात के दिनों में नुकसान का आकलन करके राम दिन अपने सर पर हाथ धरे सीने में उठे दंड़के दरमियान बैठे बैठे सोच रहा था कि , बरसात के मौसम ने मानवी गलती को स्पष्ट रूप से बताते हुए "प्रकृति" ने अपनी उपस्थिति कहां-कहां दर्ज की यह हम सब को अच्छी तरह से पता है क्योंकि, इसकी उपस्थिति के रहते कई कई शहरों में सड़क , पुल , बिल्डिंग , घर , मकान तक टूट गए या फिर पानी के सैलाब में वह एक तिनके की तरह बह गए और हम सब अपना सर पकड़ कर बैठे हुए हैं।

रामदीन मन ही मन में "मन की बात" कर ही रहा था और इतने में "सन्नाटे" को चीरती हुई एक आवाज आई रिपेयरिंग करवा लो , रिपेयरिंग करवा दो , मरम्मत करवा लो , मरम्मत करवा लो र टूटी हुई बिल्डिंग की , टूटे हुए घर की , सड़क की मरम्मत करवा लो जैसे ही यह आवाज कानों में र सकारात्मक ऊर्जा र लिए पहुंची तो मन को बहुत शांति मिली की , चलो अच्छा हुआ कोई तो आगे बढ़कर र मानव र की सहायता करने के लिए आया है। रामदीन ने उससे पूछा क्या भैया यह घर , मकान , सड़क , पुल , बिल्डिंग की मरम्मत कर दोगे।

हां न क्यौं नहीं भाई साहब मैं आवाज लगा तो रहा हूँ ? क्या आप र सरकार र की तरह हैं जो मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं ? क्या तुम्हें र कम र सुनाई देता है ? मेरे सरकार र सुनाई मैं तुम्हारे पास आया है। मैं किसी सरकार का र सरकारी र कंपनी का भंजा हुआ कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ कि मैं यहां र टाइम पास र करने आया हूँ।

अरे दादा तुम मुझे शंका भरीं नजरों से मत देखो। मैं कोई रिश्तत , भ्रष्टाचार , घोटाले , कांड

जैसी बीमारी से ग्रसित नहीं हूँ। मैं साधारण सा आदमी हूँ र लोकल वोकल र की तरह स्वास्थ्य हूँ इसलिए , आपका सहयोग करने के लिए आया हूँ और बरसात के दिनों में जो जन हानि हुई , धन हानि हुई , पशु हानि हुई , फसल हानि हुई इनमें से कुछ खाने-पीने मदद करके भरपाई जरूर कर दूंगा बस तुमसे मेरी विनती है कि , तुम भी मेरा साथ दो और मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ। र साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना र क्यौंकि , मेरे सरकार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि , यह किसी सरकारी गतिविधि के चलते आज जितने भी पूल , सड़क और बिल्डिंग आदि आदि बने हैं उन सभी में भ्रष्टाचार की र सीमेंट र के साथ रिश्तत की र ईंट र और घूसखोरी की र मिलावट र साफ-साफ दिखाई दे रही थी इसलिए इनको भाई साहब शर्म नहीं आती है।

इस विषय को लेकर फर्जी साहित्यकार पी एच डी ने कहा कि , "इनका व्यवहार ऐसा लगता है मिरजापुर जयचंद जैसा। देश से बड़ा है इन भ्रष्टाचारियों लिए पैसा ही पैसा।।"

मैं आपके पास मदद करने के लिए आया हूँ इसलिए आवाज लग रहा हूँ मरम्मत करवा लो , रिपेयरिंग करवा लो क्यौंकि मेरे सरकार किसी के भरोसे कब तक बैठे रहोगे।

" अब दुःख दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे , रंग जीवनी में नया आयो रे।" यह गीत गुनगुनाते हुआ रामप्रसाद रामदीन के साथ कई स्थानों पर स्वामिमान के चलते स्वालंबी बनकर अपने अपने नुकसान की भरपाई करने में लगाएं।

प्रकाश हेमावत

गाँव और शहर का रिश्ता कैसा हो

शम्भू शरण सत्यार्थी

मनुष्य का जीवन केवल उसके व्यक्तिगत अस्तित्व तक सीमित नहीं है, वह अपने आसपास के समाज, संस्कृति और वातावरण से गहराई से जुड़ा हुआ है। मानव सभ्यता की यात्रा आरम्भ से लेकर आज तक एक लम्बा और संघर्षपूर्ण इतिहास समेटे हुए है। इस यात्रा में गाँव और शहर दोनों की अपनी-अपनी भूमिका रही है। जहाँ गाँव ने मनुष्य को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं—अन्न, जल, आश्रय और आत्मीय संबंध—से जोड़ा, वहीं शहर ने उसे ज्ञान, तकनीक, व्यापार और आधुनिकता की राह दिखाई। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गाँव और शहर मानव जीवन के दो पंख हैं, यदि इनमें से एक की कमजोरी हो जाए तो समाज का संतुलन बिगड़ जाता है।

भारतीय संस्कृति और इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारी सभ्यता की जड़ें गाँवों में ही बोधी हुई हैं। प्राचीन काल में कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प के सहारे गाँव आत्मनिर्भर और सम्पन्न थे। यहाँ आत्मनिर्भर गाँव भारत की असली पहचान थी। यहीं से हमारी संस्कृति, परंपराएँ और मूल्यव्यवस्था की गहराई में उतरते तो पाएँ। यह हम इतिहास की गहराई में उतरते तो पाएँ।

काल के ऐतिहासिक सच्चाई पर आधारित था। यदि हम इतिहास की गहराई में उतरते तो पाएँ। कि प्राचीन भारत में गाँव और शहर दोनों का विकास साथ-साथ हुआ। सिन्धु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ और हड़प्पा जैसे नगर व्यापार और योजना का उदाहरण हैं। जबकि अरुण नदी के किनारे बसे गाँव कृषि और पशुपालन के केंद्र थे। यही संतुलन भारत को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाता था। वैदिक काल में भी अधिकांश लोग गाँवों में रहते थे और कृषि ही मुख्य आजीविका थी। गाँवों की संरचना उस

समय इतनी सुदृढ़ थी कि वे अपने भीतर छोटे-छोटे गणराज्यों के रूप में कार्य करते थे।

परंतु समय के साथ जब साम्राज्यों का विस्तार हुआ और व्यापार का महत्व बढ़ा तो नगर और महानगर भी फलने-फूलने लगे। मगध, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, वाराणसी, उज्जैन जैसे नगर अपने समय में शिक्षा और व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र बने। फिर भी गाँवों की भूमिका कभी कम नहीं हुई। नगरों को आवश्यक अनाज, दूध, कपड़ा, लकड़ी, धातु आदि सब कुछ गाँवों से ही मिलता था। इस प्रकार गाँव और शहर का संबंध एक-दूसरे के पूरक का था, न कि प्रतिस्पर्धी का।

माध्यमकालीन भारत में जब दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का उदय हुआ, तब भी गाँवों की संरचना बनी रही। किसान अपने खेतों में अनाज उपजाते और शहरी बाजारों को आपूर्ति करते। गाँवों का समाज जातियों और पेशों में बँटा हुआ था, लेकिन वह सामूहिकता और आत्मनिर्भरता से सम्पन्न था। गाँवों की यह सामूहिकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने भारत के गाँवों और शहरों को इस संरचना को गहरा आघात पहुँचाया। उन्होंने गाँवों से अनाज और कच्चा माल निकाला और शहरों में अपने कारखानों के लिए मजदूर तैयार किए। परिणामस्वरूप गाँव धीरे-धीरे निर्धन होते गए और शहर उपनिवेशवादी शोषण के केंद्र बन गए। यही वह दौर था जब गाँव और शहर के बीच का संतुलन टूटने लगा। किसान कर्ज में डूबने लगे, गाँवों की आत्मनिर्भरता खत्म होने लगी और शहरों में अमीरी-गरीबी का अंतर गहराने लगा। यही कारण था कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधीजी ने बार-बार गाँवों की ओर लौटने की बात की। गांधीजी के अनुसार भारत का पुनर्निर्माण तभी संभव है जब उसके गाँव आत्मनिर्भर और मजबूत

हों। उनका सपना था कि हर गाँव अपने भीतर छोटे गणराज्य की तरह कार्य करे, जहाँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आत्मीयता सब कुछ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो। उन्होंने चरखा और खादी को गाँव की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया। उनका मानना था कि शहरों की चकाचौंध और मशीनों का लालच मनुष्य को पतन की ओर ले जाएगा, जबकि गाँव की सादगी और श्रमशीलता उसे सच्चा सुख और शांति प्रदान करेगी।

लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत ने जिस विकास की राह पकड़ी, उसमें शहरों को प्राथमिकता मिली। उद्योग, कारखाने, आधुनिक शिक्षा संस्थान और सरकारी दफ्तर अधिकतर शहरों में स्थापित किए गए। परिणामस्वरूप गाँव पीछे छूटते गए। गाँव का युवा बेहतर रोजगार और शिक्षा की तलाश में शहर की ओर भागने लगा। इस पलायन ने गाँव को खाली कर दिया और शहरों को भीड़ और प्रदूषण से भर दिया। आज की स्थिति यह है कि गाँव और शहर दोनों ही संकट से जूझ रहे हैं। गाँव बेरोजगारी, किसानों की बढहाली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। वहीं शहर प्रदूषण, अपराध, भ्रष्टाचार, ट्रैफिक और शिक्षा देते हैं। यदि दोनों को घिर गए हैं। गाँव अपनी आत्मनिर्भरता खो चुके हैं और शहर अपनी मानवीय संवेदनार्थ।

यह विरोधाभास हमारे समाज के लिए खतरनाक है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि गाँव और शहर परस्पर विरोधी नहीं हैं बल्कि पूरक हैं। गाँव शहरों को अन्न, कच्चा माल और श्रमशक्ति प्रदान करते हैं, जबकि शहर गाँवों को आधुनिक तकनीक, बाजार और शिक्षा देते हैं। यदि दोनों का संतुलन बिगड़ता है तो समाज असंतुलित हो जाता है। यही कारण है कि आज पुनः इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है कि गाँव और शहर का रिश्ता कैसा हो और हम उन्हे किस दिशा में ले जाएँ।

एसटीईएम सिर्फ विज्ञान के छात्रों के लिए क्यों नहीं है : विजय गर्ग

लंबे समय तक, संक्षिप्त एसटीईएम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित - को उन छात्रों का डोमेन माना जाता था, जिन्होंने लैब कोट, हल किए गए समीकरण और निर्मित मशीनों पहनी थीं। यदि आप विज्ञान के छात्र नहीं थे, तो यह मान लेना आसान था कि एसटीईएम आपके लिए नहीं है। लेकिन वो मानसिकता तेजी से बदल रही है। आज की दुनिया में, एसटीईएम कौशल अब प्रयोक्ताओं या इंजीनियरिंग कार्यालालाओं तक ही सीमित नहीं है - वे लचीलापन हर क्षेत्र में सफलता की नींव बन रहे हैं।

1. डिजिटल युग की मांग है
चाहे आप एक लेखक, एक डिजाइनर, एक वकील, या एक व्यवसाय प्रेक्षक हों, प्रौद्योगिकी आपके काम को आकार देती है। कोडिंग मूल बातें, डेटा विश्लेषण, या यहां तक कि एआई टूल को समझना आपके बहुत मदद दे सकता है। उदाहरण के लिए, प्रकाशक अब कहानियों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए डेटा विज्ञान और एआई का उपयोग करते हैं, और वकील मामलों को तैयार करने के लिए भविष्य कहनेवाला विश्लेषण पर भरोसा करते हैं।

2. समस्या-विज्ञान से परे समाधान
एसटीईएम शिक्षा केवल तथ्यों और सूत्रों के बारे में नहीं है - यह महत्वपूर्ण सोच और समस्या को सुलझाने के बारे में है। ये कौशल प्रबंधन, वित्त, कला और यहां तक कि सार्वजनिक नीति के लिए फिटनेस



है। जब व्यवसायों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो नेता जो इंजीनियरों की तरह सोच सकते हैं - छोटे हिस्सों में समस्याओं को तोड़ सकते हैं और समाधान का परीक्षण कर सकते हैं - बाहर खड़े हो जाओ।

3. क्रिएटिविटी मोटेटेक्नोलॉजी
एसटीईएम और कला के बीच की सीमा धुंधली हो रही है, जिससे सटीम (एसटीईएम + आर्ट्स) को जन्म मिला है। डिजाइनर सहज ज्ञान युक्त उत्पाद बनाने के लिए इंजीनियरों के साथ काम करते हैं, फिल्म निर्माता विशेष प्रभावों के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करते हैं, और संगीतकार ध्वनि की रचना या मिश्रण करने के लिए एआई का उपयोग करते हैं रचनात्मकता आज कला और प्रौद्योगिकी के चौराहे पर पनपती है।

4. रोजगार की जिंदगी में स्टेम
डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यक्तिगत वित्त के प्रबंधन के लिए फिटनेस

को ट्रैक करने के लिए स्वास्थ्य ऐप का उपयोग करने से, हम सभी रोजाना एसटीईएम के साथ बातचीत करते हैं। एल्गोरिदम, साइबर सुरक्षा, या यहां तक कि पोषण के पीछे विज्ञान की एक बुनियादी समझ व्यक्तियों को होशियार विकल्प बनाने के लिए सशक्त बना सकती है।

5. रसायन स्ट्रीम से परे कैरियर के अवसर
नियोक्ता क्षेत्रों में एसटीईएम साक्षरता को महत्व देते हैं। विपणन टीमें उपभोक्ता डेटा का विश्लेषण करती हैं, फैशन उद्योग 3-डी प्रिंटिंग का उपयोग करते हैं, और कृषि ड्रोन और एआई को रोजगार देती है। वाणिज्य, मानविकी या कला प्रबंधन के छात्रों को बहुत फायदा होता है जब वे अपने डोमेन ज्ञान को एसटीईएम टूल के साथ जोड़ते हैं।

6. भविष्य के लिए तैयार नागरिकों का निर्माण
स्टेम समीकरणों को याद करने के बारे

में कम है और एक ऐसी दुनिया के अनुकूल होने के बारे में अधिक है जहां परिवर्तन स्थिर है। कल के कार्यबल-कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेशे को डिजिटल रूप से साक्षर, डेटा-जागरूक और वैज्ञानिक रूप से पनपने के लिए उत्सुक होने की आवश्यकता होगी।

अंतिम विचार
एसटीईएम अब विज्ञान के छात्रों के लिए एक जगह नहीं है; यह एक सांख्यिकीय कौशल है। जैसे पिछली शताब्दी में पढ़ना और लिखना आवश्यक हो गया, एसटीईएम साक्षरता 21 वीं शताब्दी की भाषा है। चाहे आप कला, वाणिज्य या सामाजिक विज्ञान का पीछा कर रहे हों, एसटीईएम को गले लगाने से रचनात्मकता, नवाचार और भविष्य के अवसर अनलॉक हो सकते हैं जो पारंपरिक सीमाओं से परे हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद,

वैश्विक ज्ञान पावरफुल में भारत का रोडमैप

विजय गर्ग

आर्थिक ताकत से परे, एक विकसित भारत की सच्ची ताकत अपने बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और नवाचार-संचालित पारिस्थितिकी तंत्र पर आराम करेगी। इसे प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए एक व्यापक रोडमैप की कल्पना की जानी चाहिए - एक जो एक समावेशी, भविष्य के लिए तैयार और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी सीखने का माहौल बनाता है।

2047 तक, जब भारत स्वतंत्रता की सदी मनाता है, तो उच्च शिक्षा एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में देश के परिवर्तन को आकार देने वाली सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक के रूप में उभरेगी। एक विकसित भारत का भविष्य न केवल उसकी आर्थिक शक्ति पर निर्भर करता है, बल्कि बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र पर भी इसका पोषण करना चाहिए। इस संदर्भ में, उच्च शिक्षा के लिए एक व्यापक रोडमैप की कल्पना की जानी चाहिए। रोडमैप को एक समावेशी, भविष्य के लिए तैयार और विश्व स्तर पर सक्षम सीखने के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना चाहिए जो नवाचार, अनुसंधान, रोजगार और सांस्कृतिक नेतृत्व को प्रज्वलित करता है। लक्ष्य भारत को विश्व स्तर पर शीर्ष तीन उच्च शिक्षा प्रणालियों में शामिल करना चाहिए, जहां उच्च शिक्षा संस्थान सामाजिक-आर्थिक विकास, सामाजिक इक्विटी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इंजन के रूप में कार्य करते हैं।

इस महत्वाकांक्षी परिवर्तन के पीछे तर्क का प्रमुख नींव पर टिकी हुई है। सबसे पहले, भारत का जनसांख्यिकीय लाभार्थी एक अवसर और एक चुनौती दोनों प्रस्तुत करता है। एक युवा और आकांक्षी जनसांख्यिकी को अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने के लिए विश्व स्तरीय, सुलभ उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है। दूसरे, जैसा कि भारत एक ज्ञान अर्थव्यवस्था में संक्रमण करता है और 2047 तक \$ 40 ट्रिलियन जीडीपी का लक्ष्य रखता है, अत्याधुनिक अनुसंधान, नवाचार और अत्यधिक कुशल प्रतिभा अपरिहार्य हो गई है। तीसरा, अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए,

भारत को 21 वीं शताब्दी में नेतृत्व करने के लिए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए एक क्वांटम छलांग लेनी चाहिए। अंत में, उच्च शिक्षा को भारत के सभ्यतागत लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करना चाहिए, जहां प्राचीन ज्ञान प्रणालियों को समकालीन सभ्यतागत विचारों के लिए अद्वितीय मूल्य जोड़ने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से मिश्रित किया जाना है। इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए एक भव्य रणनीति की आवश्यकता होती है। प्रवेश, इक्विटी, सामर्थ्य और समावेश्य इस रणनीति के अभिन्न घटक बनने चाहिए ताकि प्रत्येक इच्छुक शिक्षार्थी को लिंग, भूगोल, या सामाजिक-आर्थिक स्तर की परवाह किए बिना परिणाम-आधारित उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने का समाधान हो सके। 2047 तक, सकल नामांकन अनुपात 75 प्रतिशत तक पहुंच जाना चाहिए, जो विस्तारित संस्थानों, सामुदायिक कॉलेजों, खुले डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्मों और वॉचर समूहों के लिए लक्षित समर्थन द्वारा समर्थित है। मौजूदा विभाजक को पाटने में डिजिटल बुनियादी ढांचे और स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा सामग्री का व्यापक उपयोग महत्वपूर्ण होगा।

समावेशी के साथ, भारत को शैक्षणिक उत्कृष्टता और बहुविधयक को बढ़ावा देना चाहिए। सभी एचईआई को मौजूदा और उभरते विषयों पर लचीले, बहु-विषयक पाठ्यक्रम को अपनाना चाहिए जो राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के माध्यम से व्यावसायिक, शैक्षणिक और अनुसंधान मार्गों को एकीकृत करते हैं। एआई-सक्षम व्यक्तिगत सीखने के रास्ते से समृद्ध एक स्टैम-आधारित पाठ्यक्रम, छात्रों को भविष्य की जटिलताओं पर बातचीत करने के लिए तैयार करने में मदद करेगा। समग्रता, अंतर और ट्रांसडिसिप्लिनरी लर्निंग को विज्ञान, इंजीनियरिंग, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में इंटरफेसिंग विषयों के माध्यम से खेती की जानी चाहिए, जिससे युवाओं को वास्तविक जीवन की समस्या को सुलझाने के कौशल के साथ सशक्त बनाया जा सके।

समान रूप से महत्वपूर्ण कौशल, रोजगार और उद्यमिता के साथ उच्च शिक्षा का संकेत है। उद्योग-एकीकृत पाठ्यक्रम,

अनिवार्य इंटरनैश, प्रशिक्षित और उद्यमिता मांड्यूल को पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग बनाना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी न केवल नौकरी की तलाश कर सकें, बल्कि नौकरी भी बना सकें। सामाजिक विज्ञान स्नातकों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक उद्यमिता पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों को भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हुए स्टार्ट-अप और स्पिन-ऑफ का पोषण करना चाहिए। इसके लिए, एचईआई को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और तेजी से बदलते सीखने के परिदृश्य में कामयाब होने के लिए कौशल विकास, नवाचार और उद्यमिता के लिए रचनात्मक केंद्र बनाना चाहिए। एचईआई को महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और अन्वेषण को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए।

प्रौद्योगिकी-सक्षम उच्च शिक्षा भविष्य है। उच्च शिक्षा का एक डिजिटल और तकनीकी परिवर्तन अभूतपूर्व गति से विकास में तेजी लाएगा। प्रत्येक परिसर को डिजिटल रूप से सक्षम होना चाहिए। नैतिक और आभासी सीखने को मूल रूप से मिश्रित करना चाहिए। एआई-ट्यूटर्ड, एआर/वीआर-सक्षम लैब, और मेटावर्सल क्लासरूम शिक्षाशास्त्र को फिर से परिभाषित करेंगे, जबकि ब्लॉकचेन-आधारित क्रेडेंशियल निर्बाध वैश्विक क्रेडिट गतिशीलता सुनिश्चित करेंगे।

फिर भी एक और समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान अर्थव्यवस्था पारिस्थितिकी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण है। अनुसंधान-नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को भारत के अनुवाद अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ के रूप में काम करना होगा, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, जैव प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष और सामाजिक क्षेत्रों जैसे सीमांत क्षेत्रों में उत्कृष्टता के 100 से अधिक केंद्रों की स्थापना करता है। इन्हें विश्व स्तरीय अनुसंधान पाठों, इनक्यूबेटर और नवाचार समूहों द्वारा पूरक किया जाना चाहिए। अंतिम लक्ष्य भारत के लिए 2047 तक वास्तविक दुनिया की समस्या को सुलझाने वाले अनुसंधान उत्पादन में विश्व स्तर पर शीर्ष तीन देशों में रैंक करना है।

समग्र शिक्षा के लिए और भारत की कक्षाओं को उसके भाग्य को आकार देने के लिए केंद्रों में बदलने के लिए बड़े पैमाने पर पाठ्यक्रम, शैक्षणिक और मूल्यांकन सुधार आवश्यक है। शिक्षा के इन महत्वपूर्ण घटकों को युवाओं की शिक्षा को सीमित नहीं करना चाहिए। इसके लिए त्वरित सशोधन की आवश्यकता है, संयुक्त और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों का विस्तार करना, अंतरराष्ट्रीय परिसरों का निर्माण करना और वैश्विक मंच पर भारत की सभ्यतागत ज्ञान प्रणालियों को प्रदर्शित करना।

सफल होने के लिए इतनी महत्वाकांक्षी दृष्टि के लिए, शासन और धन सुधार आवश्यक हैं। फोकस को इनपुट-आधारित विनियमन से परिणाम-संचालित शासन में स्थानांतरित करना चाहिए, संस्थानों को जवाबदेही के साथ मिलकर स्वायत्तता का आनंद लेना चाहिए। उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को वर्तमान 4.6 प्रतिशत से जीडीपी का कम से कम 6 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए, जो परोपकार, बंदोबस्ती और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन जुटाने के पूरक हैं।

स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, HEI को हरे परिसरों में विकसित होना चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा, शुद्ध-सूच्य प्रथाओं को गले लगाना और सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित अनुसंधान करना चाहिए। प्रामाण्य विसर्जन कार्यक्रमों, सामुदायिक सेवा और सामाजिक नवाचार और उद्यमिता

परियोजनाओं में संलग्न छात्रों के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी केंद्रीय होनी चाहिए।

एक जीवंत सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र विश्व स्तर पर सम्मानित ज्ञान और नवाचार केंद्र के रूप में भारत के उद्भव के लिए केंद्रीय है। 2047 तक, भारत के सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए। उसके सांस्कृतिक परिदृश्य को अपने प्राचीन सभ्यतागत प्रवचन और आधुनिक वैश्विक दृष्टिकोण के संश्लेषण को लागू करना करनी चाहिए। सांस्कृतिक रूप से जीवंत भारत न केवल अपने स्वयं के नागरिकों का पोषण करेगा, बल्कि रचनात्मक, बौद्धिक और सभ्यतागत उत्कृष्टता में दुनिया को प्रेरित और नेतृत्व भी करेगा। इसलिए, विकसित भारत 2047 के लिए दृष्टि को समावेशिता, स्थिरता, रचनात्मकता और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक जुड़ाव पर समान जोर देना चाहिए।

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन ढांचा बनाया जाना चाहिए। इसमें नामांकन, परिणाम, रोजगार और अनुसंधान पर वास्तविक समय के डेटा की पेशकश करने वाला एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा डैशबोर्ड शामिल होगा; संस्थागत प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी; और संसद को प्रस्तुत एक वार्षिक उच्च शिक्षा रिपोर्ट। भारत की शिक्षा प्रणाली के परिणामों को 2047 तक परिवर्तनकारी होना चाहिए। भारत के विश्वविद्यालयों को विचार नेताओं, नवोन्मेषकों, उद्यमियों और सांस्कृतिक राजदूतों के उत्पादन के लिए विश्व स्तर पर बेचमार्क होना होगा। उच्च शिक्षा को भारत की \$ 40 ट्रिलियन ज्ञान अर्थव्यवस्था के इंजन के रूप में काम करने में सक्षम होना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में अपनी जगह को पुनः प्राप्त करना होगा, समावेशी, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार उच्च शिक्षा की पेशकश करनी होगी जो न केवल राष्ट्रीय प्रगति में बल्कि वैश्विक कल्याण में भी योगदान देती है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद, गली कोर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

अमृतसर में टैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एडीसीपी टैफिक अमनदीप कौर ने अपनी टीम और जोन इंचार्जों के साथ मिलकर विशेष चेकिंग मुहिम चलाई

अमृतसर, 19 सितंबर (साहिल बेरी)

इस दौरान रॉन्ग साइड पर वाहन चलाने वालों, बिना हेलमेट या ट्रिपलिंग करने वालों और चेहरा ढककर सफर करने वाले नौजवान लड़के-लड़कियों के खिलाफ बड़ी संख्या में चालान किए गए। एडीसीपी टैफिक ने कहा कि शहर में बढ़ते टैफिक हादसों को रोकने के लिए टैफिक नियमों का पालन करवाना सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी हालात में नियम तोड़ने वालों के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी।

खास तौर पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ट्रिपलिंग, बिना हेलमेट और चेहरा ढककर गाड़ी चलाने जैसी हरकतों न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि दूसरों की जिंदगी के लिए भी खतरा बनती है। टैफिक पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि वे टैफिक नियमों का पालन करते हुए अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें, गति सीमा का ध्यान रखें और रॉन्ग साइड ड्राइविंग से बचें। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आने वाले दिनों में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।



तीन दिवसीय "क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला" का आयोजन



राज्य की आय और संबंधित कुल आंकड़ों पर हुई चर्चा
11 राज्यों के 80 प्रतिनिधि हुए शामिल
अमृतसर, 19 सितंबर (साहिल बेरी)

राज्य की आय और संबंधित कुल आंकड़ों (State Income & Related Aggregates) विषय पर तीन दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन 16 से 18 सितंबर 2025 तक किया गया। इसका उद्घाटन श्रीमती जसप्रीत तलवार, आई.ए.एस., अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना), पंजाब द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री नरेन्द्र कुमार संतोषी, महानिदेशक (सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स), MoSPI, डॉ. सुभ्रा सरकार, उप महानिदेशक, नेशनल अकाउंट्स डिवीजन (NAD), MoSPI, निदेशक DES उत्तराखंड, निदेशक NBO, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली और संयुक्त निदेशक-cum-विभागा प्रमुख, DES पंजाब भी उपस्थित थे।

यह कार्यशाला नेशनल अकाउंट्स डिवीजन (NAD), MoSPI द्वारा आयोजित की गई और इसका प्रबंधन डायरेक्टर ऑफ इकॉनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स (DES), पंजाब द्वारा किया गया।

अपने संबोधन में श्रीमती जसप्रीत तलवार ने ऐसे प्रशिक्षण कार्यशालाओं की महत्ता पर जोर दिया, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के DES अधिकारियों की क्षमता और तकनीकी कौशल को मजबूत करने में सहायक होती हैं।

महानिदेशक (सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स) ने

राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) की तैयारी में बॉटम-अप अप्रोच अपनाने पर बल दिया। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को MoSPI की नई पहलों, विकाससात्वक प्रयासों और सर्वेक्षणों के बारे में भी अवगत कराया।

उप महानिदेशक (NAD) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया कि वे बेस ईयर रिवीजन के लिए आवश्यक जानकारी 15 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराते हुए पूर्ण सहयोग दें।

कार्यशाला के मुख्य सत्रों में राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के आकलन के लिए प्रयुक्त वर्तमान पद्धति और बेस ईयर रिवीजन के दौरान की जाने वाली संभावित परिवर्तनों पर चर्चा की गई।

इस समारोह में लगभग 80 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो 11 राज्यों—हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, गुजरात, तेलंगाना और मेजबाबन राज्य पंजाब—से आए थे। इसके अलावा MoSPI के नेशनल अकाउंट्स डिवीजन के अधिकारी भी उपस्थित थे।

यह कार्यशाला ज्ञान साझा करने, क्षमता विकास करने और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण मंच सिद्ध हुई।

18 सितंबर 2025 को हुए समापन सत्र में श्रीमती जसप्रीत तलवार ने अतिरिक्त महानिदेशक, नेशनल अकाउंट्स डिवीजन, MoSPI, आर्थिक सलाहकार, DES हिमाचल प्रदेश सरकार, संयुक्त निदेशक DES तेलंगाना एवं गुजरात और सहायक निदेशक, NSSO, SRO अमृतसर ने उपस्थिति दर्ज कराई।

डिप्टी कमिश्नर ने पराली न जलाने वाले किसानों को "हीरो किसान प्रशंसा पत्र" देकर किया सम्मानित

कहा - पराली को आग न लगाने वाले किसानों के सरकारी कार्य होने प्राथमिकता के आधार पर सेवा केंद्र में बनाए गए प्राथमिकता कार्ड काउंटर का किया उद्घाटन किसानों ने प्रशासन का जताया धन्यवाद

अमृतसर, 19 सितंबर (साहिल बेरी)

डिप्टी कमिश्नर श्रीमती साक्षी साहनी ने आज मजिस्ट्रेट हल्के के गांव सोहिया कलां और अजेबवाली में किसानों के खेतों में पहुंचकर जिले के छोटे और सीमांत किसानों, जिन्होंने पराली को आग नहीं लगाई, को विशेष रूप से "हीरो किसान प्रशंसा पत्र" देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि "आप हमारे हीरो हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं।"

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पराली को आग न लगाने वाले किसानों के सरकारी काम प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। उन्होंने आज सेवा केंद्र में किसानों को दिए जाने वाले प्राथमिकता कार्ड काउंटर का



उद्घाटन भी किया और किसानों को प्राथमिकता कार्ड वितरित किए। उन्होंने बताया कि ये प्राथमिकता कार्ड सेवा केंद्रों, फर्द केंद्रों और अन्य सरकारी कार्यों के लिए उपयोग किए जा सकेंगे, जहां किसानों के कार्य पहले निपटाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सरकारी दफ्तरों में इन किसानों को निःशुल्क पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी।

श्रीमती साहनी ने बताया कि इसके अलावा प्रशासन

द्वारा खेती के उपकरण बेचने वाली निजी कंपनियों से भी तालमेल किया गया है, ताकि पराली को आग न लगाने वाले किसानों को कृषि उपकरणों पर विशेष छूट दी जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अन्य निजी कंपनियों से भी संपर्क किया गया है जो प्रगतिशील किसानों को अपने सामान पर छूट प्रदान करेंगी। इसके अतिरिक्त इन किसानों को सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में विशेष निमंत्रण पत्र भेजे जाएंगे ताकि वे इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकें।

इस मौके पर उपस्थित किसानों ने डिप्टी कमिश्नर का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा दिया गया प्राथमिकता कार्ड हमारे लिए गर्व की बात है। यह पहल अन्य किसानों को भी प्रेरित करेगी कि वे पराली को आग न लगाएं। इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर श्री रोहित गुप्ता, कृषि विभागा से डॉ. प्रमन कुमार, श्री तेजेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

5000 रुपये रिश्वत लेते सहायक सब-इंस्पेक्टर को विजिलेंस ब्यूरो ने किया काबू

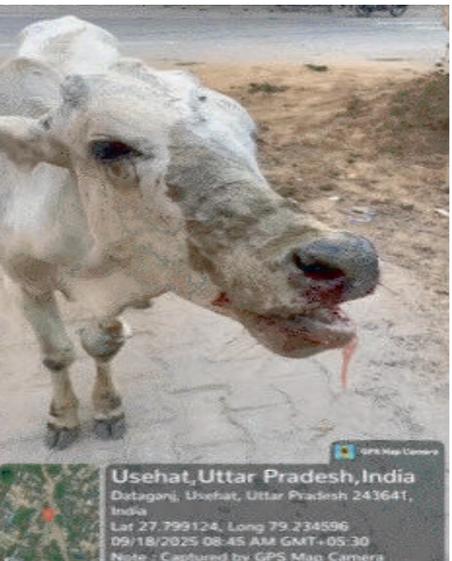


आरोपी रिश्वत की पहली किस्त के रूप में ले चुका था 16,000 रुपये
अमृतसर 19 सितंबर (साहिल बेरी)

राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने थाना-एडिबीजन, अमृतसर में तैनात सहायक सब-इंस्पेक्टर (ए.एस.आई.) तलविंदर सिंह को 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त पुलिस मुलाजिम को अमृतसर के एक निवासी द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के

आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो से संपर्क कर आरोप लगाया कि वह एक होटल की देखरेख करता है और पुलिस ने होटल के खिलाफ मामला दर्ज करके मोबाइल फोन और डी.वी.आर. जब्त कर लिए थे। शिकायतकर्ता ने कहा कि जब वह फोन और डी.वी.आर. वापस लेने के लिए उक्त ए.एस.आई. से मिला तो ए.एस.आई. ने इसके बदले 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की, लेकिन बाद में 30,000 रुपये पर राजी हो गया। आरोपी ए.एस.आई. ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 16,000 रुपये नकद लिए और शेष

14,000 रुपये किस्तों में लेने के लिए सहमत हो गया। प्रवक्ता ने बताया कि इस शिकायत की पड़ताल के बाद, अमृतसर रेंज की विजिलेंस ब्यूरो की एक टीम ने जाल बिछाया और ए.एस.आई. तलविंदर सिंह को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से रिश्वत की दूसरी किस्त के रूप में 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत विजिलेंस ब्यूरो थाना अमृतसर रेंज में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की आगे की जांच जारी है।



उसैहत में कटरा चौराहे के पास एक बस चालक ने लापरवाही द्वारा बस चलाते हुए सड़क किनारे बैठी गाय के टक्कर मार दी, जिससे गाय का जवड़ा टूट गया, स्थानीय लोगों ने बस रोकने की कोशिश की परन्तु बस नहीं रुकी, राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बस का नंबर लेकर थाना उसैहत में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया।

मुगल और ब्रिटिश शासन काल में पंजाब और पंजाबी पहचान उजाड़ दी गई थी, लेकिन हर बार पंजाब ने आपदाओं को हराकर जीत हासिल की। उसी तरह आज भी बाढ़ की तबाही को हराकर पंजाबी पहचान जीत दर्ज करेगी - धालीवाल

*अमृतसर/अजनाला, 19 सितंबर (साहिल बेरी)

विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब श्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अजनाला क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को पुनर्वास का भरोसा दिलाते हुए कहा कि मुगल काल और ब्रिटिश शासन के दौरान पंजाब और पंजाबी पहचान पर जुल्म ढाए जाते रहे, जिससे पंजाब उजड़ता रहा। प्राकृतिक आपदाओं से भी तबाही होती रही, लेकिन पंजाब एकजुटता ने हर बार पंजाब को फिर से खड़ा किया। उसी तरह अब भी भयंकर बारिशों और विनाशकारी बाढ़ से सामाजिक और आर्थिक रूप से तबाह हुए पंजाब के पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने रमिशन चढ़दी कलार स्थापित किया है। इसके तहत पूरे देशवासियों और खासकर विदेशों में बसे दानी पंजाबी एक परिवार की तरह रहे पुनर्वास अभियान के दौरान सोमा क्षेत्र के गांव कोट राजदा और सुफिया आदि में प्रभावित परिवारों को समर्थन देने और नुकसान का जायजा लेते हुए व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि रमिशन चढ़दी कलार के तहत ही मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह

मान ने 26 से 29 सितंबर तक पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में केंद्र सरकार की राहत नीति के तहत वर्तमान में दी जा रही सहायता राशि जैसे - * फसलों के 100% नुकसान पर 6800 प्रति एकड़ मुआवजा, * मृत पशुओं पर प्रति पशु 37,500, * क्षतिग्रस्त घरों पर 40,000, * और बाढ़ में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को 2-2 लाख

इन सभी मुआवजों में पंजाब सरकार संशोधन करके बढ़ोतरी की मांग करेगी ताकि पंजाब के पुनर्निर्माण के लिए वास्तविक सहायता मिल सके। उन्होंने बताया कि बाढ़ ने पंजाब के 23 जिलों के 2300 से अधिक गांवों को प्रभावित किया है, जिनमें 3200 स्कूल, 1400 स्वास्थ्य केंद्र, 8500 किलोमीटर सड़कें, 2500 पुन-पुलिया, पंचायत घर, और 20 लाख से अधिक लोग शामिल हैं। साथ ही 56 लोगों की मौतें और सैकड़ों पशुओं की मौतें हुई हैं। इस नुकसान की भरपाई के लिए फसलों पर 20,000 प्रति एकड़ और घरों व पशुओं के मुआवजों में भी उचित वृद्धि की जा सकती है।

देश का भविष्य युवाओं के हाथों में: प्रोफेसर करमजीत सिंह, कुलपति, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर

गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करमजीत सिंह ने युवक सेवाएँ विभाग और पंजाब एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा आयोजित रेंड रन मैराथन को हरी झंडी दिखाई - प्रथम तीन विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया
अमृतसर, 19 सितंबर (साहिल बेरी)

युवक सेवाएँ विभाग, पंजाब और पंजाब राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सहयोग से, आज गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में युवक सेवाएँ विभाग के सहायक निदेशक, प्रीत कोहली के नेतृत्व में रेंड रन मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन को मुख्य अतिथि प्रोफेसर करमजीत सिंह, कुलपति, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेंड रन क्लबों के 150 से अधिक स्वयंसेवकों ने इस 5 किलोमीटर की मैराथन में भाग लिया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि युवा किसी भी देश की रीढ़



होते हैं। देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है और उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान समय में नशाखोरी और एड्स जैसी गंभीर चुनौतियों से बचाव के लिए जागरूकता सबसे सशक्त माध्यम है। कुलपति ने युवा सेवाएँ विभाग के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इस तरह की गतिविधियों निरंतर जारी रहनी चाहिए ताकि युवाओं को एड्स जैसी भयानक बीमारी से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि आज की मुख्य आवश्यकता जागरूकता है। जागरूकता के माध्यम से ही हम स्वयं और समाज को स्वस्थ रख सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इस तरह के जागरूकता अभियान चलते रहने चाहिए। मैराथन के विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। लड़कियों में खालसा कॉलेज फॉर विमेन अमृतसर की कोमलप्रीत कौर ने पहला, खालसा कॉलेज फॉर विमेन अमृतसर की रिया सेवाएँ विभाग के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इस तरह की गतिविधियों निरंतर जारी रहनी चाहिए ताकि युवाओं को एड्स जैसी भयानक बीमारी से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि आज की मुख्य आवश्यकता जागरूकता है। जागरूकता के माध्यम से ही हम स्वयं और समाज को स्वस्थ रख सकते हैं।

को संयुक्त रूप से क्रमशः 4,000 रुपये, 3,000 रुपये और 2,000 रुपये के पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के युवक कल्याण विभाग के डीन प्रोफेसर हरविंदर सिंह सैनी और डॉ. कमलेश गौलेरिया विशेष रूप से उपस्थित थे। युवा कल्याण विभाग के निदेशक और शिक्षा विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अमनदीप सिंह ने अपने कुशल नेतृत्व से इस विनी मैराथन को सफल बनाया। इस अवसर पर प्लेसमेंट निदेशक डॉ. अमित चोपड़ा, डॉ. अमरिंदर सिंह, डॉ. परमिंदर सिंह, डॉ. सैना, डॉ. अशदीप सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।